HARYANA VIDHAN SABAD

DEBATES

24th July, 1968

Vol. I—No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 24th July, 1968

	Page
Absence of the Speaker	(7)1
Starred Questions and Answers	(7)1
Call Attentin Notices	(7)8
Statement made by the Irrigation and Power Minister Demands for Grnts-	(7)9
19-General Administration	(7)10
31-Agriculture	(7)10
34-Co-Operaton	(7)11
35-Industries	(7)11
Walk-Out	(7)48
Demands for Grants (Resumption)	(7)48
Extensionof the sitting	(7)55
Demands for gants (Resumption)(Concld)	(7)56

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 7,

DATED 24TH JULY, 1968

शुद्ध	अशुद्ध	पृष्ठ	लाईन
वे	वे	(7)7	13
चोरी	धोरी	(7)7	5 से नीचे
स्पीकर	स्पीकर	(7)8	3
पंजाब	पंजाब	(7)22	7
अपील	अपील	(7)22	10
पड़ता	पड़ता	(7)22	6 से नीचे से
At	As	(7)23	8 नीचे से
नये	नये	(7)28	23
मुकरर्र	मुकरर्र	(7)36	19

बेच	बेंच	(7)38	10
आदमियों	आदमियों	(7)38	11
है	है	(7)39	5
उपाध्यक्षा	उपाध्यक्षा	(7)49	14
भाईयों	भाईयों	(7)51	19
साहिबा	साहिबा	(7)52	16

HARYANA VIDHAN SABHA

Wednesday, the 24th July, 1968

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, VidhanBhavan Chandigarh, at 2-00 P.M. of the Clock, Deputy Speaker (Shrimati Lekwati Jain) in the Chair

ABSENCE OF THE SPEAKER

Secretary: In pursuance of clause(3) of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have to inform the House the Mr. Speaker is unavoidably absnet. The Deputy Speaker will therefore, take the Chair

(At this Stage Deputy Speaker occupied the Chair)

Deputy Speaker: Question hour please.

STARRED QUESTIOS AND ANSWERS

Government Employees on Hunger strike

*20 **Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be please to State-

(a) Whether the Government employee who resorted to hungers trice have since been released;

(b) Whether The Government held out any promise to the employees referred to in part (a) above to the effect that in the event of their withdrawing the agitation no victimization would be done;

(c) If the replies to parts (a) and (b) above be in the negative and affirmative, respectively, the reasons for not releasing the said employee, so far?

Shri Bansi lal: (a) Yes. The Offence being bail able, the arrested employees were released as soon as they offered bail.

(b) No.

(c) Question does not arise.

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि जब सरकारी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल रखी हुई थी, उस हड़ताल को खत्म कराने के लिए क्या कोई सरकारी प्रवक्ता वहां गये थे और उन्होने कोई वायदा, प्रामिअ या एश्योरेंस दी थी?

मुख्य मंत्रीः डिप्टी स्पकर साहिबाा, इसका जवाब मैने दे दिया है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने बिल्कुल रैलेवेंट सवाल पूछा है,उनकी नालेज में यह बात होनी चाहिये मगर कहते है कि मै जवाब दे बैठा हूं। मैने जो प्रश्न किया था उसका यह जवाब नही है। जो इन्होने दिया है। यह बात प्रैस में आ चुकी है ओर पब्लिक इंट्रैस्ट की बात है। मै कहता हूं कि मेरी सप्लीमेंटरी का जवाब दे।

मुख्य मंत्रीः गवर्नमेंट प्रैस की खबरों की जिम्मेदार नही है।

"Whether the Government held out any promise to the employees and I have replied "No"

श्री फतेह चन्द विज: क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि क्या श्री खुरशीद अहमद, स्वास्थ्य मंत्री, कर्मचारियों से बातचीज करने के लिये वहां गये थे?

मुख्य मंत्री: जी नही।

श्री मंगल सैन: क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये सरकार कोई इरादा रखती है?

मुख्य मंत्री: कोई आदमी हो उससे सरकार हर मुनासिब बात पर बातचीत करने के लिये तैयार है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने यह स्पैसिफिक क्वैस्चर किया है कि कर्मचारियों की मांगों परक्या आप गौर करेंगे या नही?

मुख्य मंत्री: मैने जवाब दे दिया है।

Case Registered President, Haryana pradesh Congress

*21. **Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state, any case has been registered against the

present Prudent of Haryana Pradesh Congress with Police Station Dadri ; if so, the section under which the said case has been registered together with the present state there of?

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा मैने मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहा कि श्री राम कृष्ण गुप्ता जो प्रदेश है उनके खिलाफ क्या दफा 409 के तहत कोई मुकदमा दायर है? इन्होने इस सवाल का जवाब दिया कि मामले कि तहकीकात हो रही है। मै पूछना चाहता हूं कि इस तहकीकात की क्या स्टेज है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या नही?

मुख्य मंत्री: मैने जवाब दे दिया है, इससे आगे जवाब नही देना चाहता क्यों यह मामला अण्डर इन्वैस्टीगेशन है।

श्री मंगल सैन: यह कब तक होने की आशाा है।

Chief Minister: As soon as possible.

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहिबा 'ऐज सून एज पासिबल' वाली जो टर्म है वह बड़ी वेग है, गवर्नमेंअ अपने सारे गुनाह इस की ओट मं छिपा लेती है।

Complaint against S.H.O., Rania, Tehsil Sirsa,District Hissar

*22 **Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government have received and telegram or memorandum against the excesses done by the S.H.O., Rania, Tehsil Sirsa, District Hissar ; if so, the contents there of and the action taken by the Government thereon?

Shri Bani Lal: Yes The main allegation contained in the telegrams and complaints are:-

(i) Highhandedness and harassment of small Jan Sangh landowners;

(ii) Instigation of their tenants to reoccupy land;

(iii) Attempt to disturb a Jan Snagh public meeting at Rania ; and

(iv) Motivated attack by Good as on Sarpanch, Rania.

The Allegations of highhandedness including beating of some Jan Sangh workers ect. are the subject of complaint in the court of Judicial Magistrate, 1st Class, Sirsa and the Matter is, therefore, subjudice.

No allegations against Police has been substantiated

A Case FIR No. 53, dated 26th June, 1968 under section 149/379/506 IPC has been registered at Police Station

Rania on the complaint of attack on the Sarpanch which is under investigation. The assumed have since been arrested.

श्री मंगल सैन: मै जानना चाहता हूं कि क्या उन्होने बुलाकर पूछा है कि जो कुछ तुम ने अलैज किया है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या आप ने उने इस सम्बन्ध में बातचीत की है?

मुख्य मंत्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो स्पैसिफिक ऐलीगेशन्ज थे उनके बारें में अदालत में केस चले गये है। जो जनरल कम्पलेट्य पंलिस के बारें में थी उनके बारे में इन्क्वायरी की गई थी।

श्री मंगल सेन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि इन्क्वायरी की थी। क्या वे बतायेगे कि इन्क्वायरी करने के लिये कोन कौन से आफिसर लगाये गये थे। यह बड़ा सीरियस मामला है, कोई घरका मामला नही है।

मुख्य मंत्री: बिल्कुल कानूनी और मुनासिब ढंग से इन्क्वायरी की गई थी।

श्री मंगल सैन: मै जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने इन्क्वायरी की है उसका डैजिगनेशन क्या है।

मुख्य मंत्री: मै समझता हूं यह बताना जरूरी नही है कि किस ने इन्क्वायरी की है।

चौधरी चांद राम: मेरे ख्याल में मुझे मास्टर बनना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कृपया देखिए कि पार्ट ''बी'' में लिखा हुआ है: "to supply drinking water to the village referred to in part (a) above". and not where there is water scarcity. The reference was to part (a), i.e. "where is not all available" and the Chief Minister replied that there are no villages. What was the necessity of framing schemes when there were no villages to benefit from these schimes?

मुख्य मंत्री: मैने तो कहा कि जहां एक्यूट शार्टेज थी, वहां कि लिय स्कीमों बनाई गइ है।

Ch. Chand Ram: I am happy that he has corrected hi reply.

श्री फतेह सिंह विज : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि पहले उन स्कीमों के ऊपर काम शुरू किया जाएगा जो पैसे न होने की वजह से नामुकम्मल पड़ी है या नहई स्कीमों पहले शुरू की जाएंगी?

मुख्य मंत्री: जहां ज्यादा जरूरत होबी वहां पहले काम किया जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हिसार और महेन्द्रगढ़ के जिन गांवों में पीने

की बड़ी तक्लीफ है उन सबको इन सारी योजनाओं में शामिल कर लिया गया है?

मुख्य मंत्री: सबके सब गांव तो इन योजनाओं में शामिल नही लेकिन जैसा मैन पहले बताया है कि स्टेट के अन्दर जहां कही भी स्कीम मे शामिल गांवों की अपेक्षा ज्यादा जरूरत समझी जाएगी वहां पहले पानी दिया जाएगा।

श्री दया कृष्ण: क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सैन्टरल गवर्नमेंअ से पैसा लम्प सम में मिलता है या जो खर्च कियाजाता है उसकी परसैन्टेज के हिसाब से मिलता है?

मुख्य मंत्री: गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लैनिग कमीशन के बनाए हुए कुछ नियम है, उनके तहत मिलता है, अब नए नियम बनाए जा रहै जिनमे कि यह भी फैसला होगा कि किस हिसाब से मिलेगा।

Ch. Chand Ram: May I know what is the definition of drinking water according to the Chief Minister or the Government?

मुख्य मंत्री: पीने का पानी।

उपाध्यक्षा: चौधरी चांद राम जी इसकी डैफिनीशन तो सब ही जानते है। इसमे पूछने की क्या बात है?

Declaring Palwal Areas as in Industrial Colony

*35 **Shri Roop Lal Mahta:** Will the Chief Minister be released to state whether Government is considering any proposal to declare Palwal areas as un Industrial colony

Shri Bansi lal: No.

श्री रूप लाल महता: क्या चीफ मिनिस्टर बताएंगे कि सरकार वहां कोई इंडस्ट्री लगाने मे मदद देगी, यदि यह उसे इंडस्ट्रियल ऐरिया डिकलेयर नही कर सकते?

मुख्य मंत्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोगों की डिमांड को कंसिडर करने के बाद यदि सरकार मुनासिब समझेगी तो जरूर मदद दी जाएगी।

Setting Up a 'Grid Sub-Station a Badhra in Tehsil Dadri, District Mohindergarh.

*15. Shrimati Chandravati: Will the Minister for Irrigation and Power be please be pleased to state whether any Grid Sub-Station is proposed to be set up at Badhra in Tehsil Dadri, district Mohindergarh ; if so, the date by which the same is likely to be set up?

Shri Ram Dhari Gaur: No

श्रीमती चन्द्रावती: क्या सिंचाई मंत्री बताएंगे कि बाडढा के आस पास` गांव को बिजली की क्या कोई स्कीम है यदि है तो क्या बे उस स्टेशन का नाम और वहां से दूरी बताएंगे जहां से बिजली दी जाएगी?

मुख्य मंत्री: बाडढ़ा के एक तरफ तो झौझू कलां है और दूसरी तरफ दादरी है जहां से नजदीक पड़ेगा और साथ ही यदि बिजली देना ठीक समझा जाएगा वहां से बिजली दे दी जाएगी।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में वहां क्या कोई सब–स्टेशन बनाने की योजना है?

मुख्य मंत्री: यदि उस एरिया में जरूरत होगी तो सरकार उस पर जरूर गौर करेगी।

Construction of A Rural Road from Palwal to Ghori in Palwal Constituency

*37. **Shri Roop Lal Mehta:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government is considering to construct a Road from Palwal to Ghori in Palwal Constituency to provide the residents of that area better means of communication to bring their produce in the market.

Shri K.L. Poswal: There is no proposal to construct the road from Palwal to Ghori at present due to paucity of funds.

श्री रूप लाल महता: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जकि मार्किटिग कमेटी ने पलवल से धोरों तक रोड़ के लिए रूपया में जमा करा दिया हुआ है तो फिर भी उस रोड को क्यो नही बनाया जा रहा है?

लोक कार्य मंत्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो रोड़ है यह विलेजिज रोड में आती है इसमें जब तक गांवा लो 1/4 शेयर अपना जमा नही करते तब तक इसको कन्सिडर नही कर पायेगे। अगर जमा करा दिया है तो पाजिटिवली कन्सिडर करेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोल: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जिन गांवों ने अपनी सड़कों के हिस्स के रूपए जमा कर दिये है उनकी सड़के बनवाई जायेंगी?

मंत्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने पहले ही यह अर्ज किया है कि पाजिटिवली कन्सिडर करेंगे, क्योंकि बहुत से गांवों ने इस तरह के शेयर जमा करा दिये है।

Provincialisation of Municipal Hospital, Palwal

*36. **Shri Roop Lal Mehta:** Will the Minister for Health be pleased to state whether Government is considering any proposal to take over the Municipal Hospital at Palwal?

Ch. Khurshed Ahmed: The Municipal Civil Hospital, Palwal, will be provincialised during the year, 1970-71 in case the Draft 4th Five year Plan as proposed by the Haryana Health Department is approved by the Planning commission.

श्री रूप लाल महता: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इसकों प्रोविन्शिलाइज करने में सरकार को क्या दिक्कत है?

स्वास्थ्य मंत्री: केवल फन्डज की दिक्कत है।

श्री फतेह चन्द विज: आप महता साहब के जवाब में नो नो कहकर ऐसी बगावत कराने की बातें कर रहे है।

मंत्री: आप भी तो बिल्कुल बागी है आपके लिए भी तो कभी कभी 'यस' कही जाती है।

Call Attention Notice

Deputy Speaker: The House will now take up Call Attention Notices.

Call Attention Notice No. 11 is from Sarvshir Fateh Chand Vij, allotment of Government quarters to the Haryana

Government employees, in the Union Territory, Chandigarh. I would request one of the honorable Members to read out the notice

Shri Fath Chand Vij: Sir, I beg to draw the attention of the State Government to the fact that there is great injustice in the allotment of the Government quarters to the Haryana Government employees in the Union Territory, Chandigarh, because usually the Government quarters have been allotted to Punjab Government employee and the Haryana Government employees are suffering a lot. So this motion moves that in the Government Quarter Allotment committee either the Chief Secretary or any other responsible officer be deputed to safeguard the interests of Haryana Government employees in the allotment of Government Quarters. The Government should take immediate step in this direction to remove this injustice. One senior member of Allotment committee has resigned from the membership of the said Committee.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यूनियन टेरेटरी के अन्दर जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होने उस हाउस एलाटमैंट से रिजाइन कर दियाहै। वे उस कमेटी के सीनियर मेम्बरेां में से थे क्योंकि पंजाब वालों ने वहां पर ऐसी धांधली मचायी हुई है। कि हरियाणा के लोगों को चार चार साल हो गये है दरखास्त दिये हुए लेकिन उनको ंक्वार्डर एलाट नही किय जाते है। तो मैं गवर्नमैंट से यही प्राथ्रना करता हूं कि उन क्वार्टरों को जो हमारे हिस्से के है अपने कब्जा मे ले लें ताकि अपने मुलाजिमों को जो दिक्कत है उसकों

हम दूर कर सकें। तो वहां पर कोई अफसर भेजें जो इस विषय में पूरा ध्यान रखें।

Deputy Speaker: The notice is admitted. The Minister concerned is requested to make as statement.

Chief Minister: I will make a statement on the 29th July, 1968.

Deputy Speaker: There is another Call Attention Notice No. 12 from Shri Mangal Sein regarding pay scales of Hindi and Sanskrit teachers. This notice is disallowed on the round that it is not a matter of urgent public importance.

Statement made by the Minister for Irrigation and Power

Deputy Speaker: As promised yesterday by the Irrigation and Power Minister, he may please make a statement on Call Attention Motion No. 10.

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): It is true that some parts of the State have been inundated as a result of continuous and intensive rainfall but here has been no negligence on the part of the Irrigation Department. On the Other hand, the Irrigation Department took all possible measures to protect the areas and properties of the state against floods within the available resources an the position this year is better than in the last year. No serious complaints have been received form areas worst affected during the 1967 floods like Hodal Palwal aread in

District Gugaon and Jhajjar and Gohana areas in Wazirpur, District Rohtak.

2. The Ambala-chandigarh roads falls partly in Punjab and partly in Haryana. There are various cause ways in the portion passing through Punjab where water level arose considerable thus dislocation vehicular traffice. It is understood that the Punjab authorities are taking up the question of raising this road with the Government of India. No breach occurred in this road in portions falling in Haryana. Breaches , however, occurred on some other roads in Haryana. On the Ambala-Pehwa road near the crossing of Tangri and Narwana Branch, three breaches occurred. The Narnaul-Mohindergarh-Dadri road has also been affected. Due to the breach in the Daily bund on the left bank of Markanda, the ShahbadBrara-Nahan road has been washed out at places. Work to Plug the breaches on the bunds and roads will taken up a soon as conditions permit.

3. The exact figures of damages to crops and property have not been received and efforts are being made to obtain these from the field officers.

4. I would like to assure the House that Government is fully alive to the problems posed by the floods. Whatever action is necessary will be taken promptly.

Deputy Speaker: The House will take us Demand No. 9 relating to 19-General Administration.

श्री दया कृष्ण: डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के सामने चार मोशन है अगर ये चारों मोशन इक्ट्ठी मूव कर दी जाये तो

इससे हाउस का टाइम भी बच जायेगा और मेम्बर इनही मोशंज पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

Deputy Speaker: Yes, it is a good suggestion

DEMNDS NO. 9

19-GENERAL ADMINSISTRATION

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Madam, I beg to move-

That a sum not exceeding Rs. 1,31,96,090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding he amount of Rs. 64,16,940 already voted on account) in respect of charges under the head 19-GENERAL ADMINISTRATION.

Deputy Speaker: Motion moved-

That a sum not exceeding Rs. 1,31,96,090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding he amount of Rs. 64,16,940 already voted on account) in respect of charges under the head 19-GENERAL ADMINISTRATION

There is a Cut Motion give notice of by Shri Roop Lal Mehta, viz-That the demand be reduced by Re 1."

It will be deemed to have been read and moved and con be discussed along with the main motion

Further, I think the hon. Members would agree with me that tall the Demands and the Cut Motions there to, if any, be moved now and then be discussed together. Of course, at the ends of the discussion they will be put to the vote of the House separately.

DEMAND NO. 9

31-AGRICULTURE

Labour Minister (Ch. Ran Singh): Madam, I beg to move-

That a sum not exceeding Rs. 2,61,17,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 1,30,00,000 already voted on account) in respect of charges under head "31-Agriculture".

Deputy Speaker: Motion moved-

That a sum not exceeding Rs. 2,61,17,610 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 1,30,00,000 already voted on account) in respect of charges under head "31-Agriculture".

DEMNAD NO. 21

31-CO-OPERATION

Development Minister (Rao Mahabirsingh): Madam, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 39,18,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 18,00.000 already voted on account) in respect of charges under head 31-Co-operation.

Deputy Speaker: Motion moved-

That a sum not exceeding Rs. 39,18,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 18,00.000 already voted on account) in respect of charges under head 31-Co-operation.

DEMAND NO. 22

35-INDUSTRIES

Chief Minister (Shri Bansi Lal): Madam, I beg to move-

That a sum not exceeding Rs. 6254580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 40,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 35-Industries.

Deputy Speaker: Motion moved-

That a sum not exceeding Rs. 6254580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 40,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 35-Industries.

There is a cut motion to this demand given notice of by Shri Roop Lal Mehta, viz-

"That the demand be reduced by Re 1."

It is also deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main motion.

Now hon. members may speak on these demands, but before speaking every hon. Members will indicate on which demand he intends speaking

Further hon. Members are requested to speak for ten minutes each and finish the debate by 5.15 P.M.

मै चाहती हूं कि हर एक मेम्बर दस मिनट से ज्यादा न बोले। सवा पांच बजे मेम्बर्ज को स्पीचिज खत्म करनी होगी, क्योंकि मै पौना घंटा मिनिस्टर्ज को जवाब के लिए देना चाहती हूं। फिर आधा घंआ इन डिमांइज को पस करवाने में भी लगेगा। मै उम्मीद करती हूं कि हाउस मेरे साथ सहमत होगा।

मलिक मुख्तियार सिंह (सोनीपत): मैडम डिप्टी स्पीकर, आज जो चार डिमांड्ज हमारेसामने है, वह बड़ी इम्पाटैट है। दस मिनट तो हर डिमांड पर बोलने के लिए लगेगे और 40 मिनट कम

से कम होने चाहिए। फिर ीाी जैसे आपेन कहा है मै जल्दी खत्मक करने की कोशिश करूंगा।

मैडम, जनरल बजट पर बहस मुबाहसा के बाद आज चार इम्पाटेंट डिमांड्ज हमारे सामने पास करने के लिए आई। वैसे तो आपने जो टाइम मुकर्रर कियाहै उसके हिसाब से तो किसी एक डिमांड को भी अच्छी तरह से टच नही किया जा सकता। लेकिन फिरभी मै तो तीन डिमांड्ज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीच, पर हाउस के सामने अपने जो ख्यालात है और जो मेरा नजरिया है वह आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं।

मैडम डिप्टी स्पीकर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह सूबे का नजमोनसक होता है। हर एक आदमी चाहता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पाक ओर साफ होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा जिसे एक यंग स्टेट कहा जाता है, एक इन्फेंट स्टेट कहा जात है, उसकों वजूद में आये हुए केवल दो साल हुए है। मै तो यह समझता हूं कि हरियाणा के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन की जो हालत है वह बिल्कुल नागुफताबे हैं और इस चीज को को देखे हुए हमेंअफसोस होता हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, जितनी कुरप्शन हमारे सूबे के अन्दर बढ़ती जा रही है और जिस तेज रफ्तार से यह चल रही है उसकों देखकर हरेक आदमी को पशेमान होना पड़ता है। हर एक आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको बढ़ावा देने के लिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत बड़े बड़े आदमी शामिल है। मै तो यह कहूंगा कि इस सूबे के अन्दर

सियासतदानों से लेकर, वजीरों से लेकर इसमें सभी लोग शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुरप्त करने मे इसमें उन सब लोगो का हिस्सा है। जिस सूबे के अन्दरयह हालात हों और वजीर इस हद तक पहुंच जाएं तो उस सूबे का क्या हाल होगा। मेरा तो विश्वास है कि आजकल के दिनों में कोई कुरप्शन नही कर सकता जब तक कि उसके ऊपर कसी वजीर या दूसरे बड़े आदमी का हाथ न हो। क्योंकि उनके जरिए यह करप्शन होता है, छोटे आदमियों का तो कहना ही क्या हैं कुछ वजीर साहिबान अफसरों का अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते है जिसका नतीजा होता है कि फिर एक दूसरे को ऐक्सप्लयातट करत`है। अगर किसी वजीन ने एक बारकोई काम किसी अफसर से नाजायज करा लियातो फिन वही अफसर अपने 10 नाजायज काम करवाता है। और वजीर की हिम्मत नही होती है कि वह उसकों चैक कर सकें। मुझ जनाबस एक शेयर याद आया है–

जब तूफान में हो किश्ती तो याद आती है तदबीरे

मगर जब किश्ती में तूफां हो ता मिट जाती है तकदीरे

जब वजीरों और बड़े आदमियों की यह हाल हो तो फिर सूबे के लोगों का क्या होता? डिप्टी स्पीकर सहिबा, हरियाणा के अन्दर इंसाफ नही मिलता और जिस किसी भी चीज का

डिसीजन किया जात है वह पेालिटीकल लैवल पर किया जात है और पोलिटीकल डिसीजन ही नही पोलिटीकल विकटेमाइजेशन हभी एक इन्तहा पर जा चुकी है। मै चंगेज खां ओर नादिरशाह का तो नाम नही लेता लेकिन मैने कैरों शाही जरूर देखी है। और यह गवर्नमैंट अभी थोड़े से अरसे में ही जिस ढंग से चल रही है उसकों देख कर मै समझता हूं कि जितनी बिकटेमाइजेशन इन्होने कर दी उतनी कैरोंशाही के सारे जमाने मे नही हुई होगी। वह तो किसी तरीके से करते थे लेकिन यह जो करते है उसमें तो बिल्कुल ही अनाड़ीपन हैं कल एक सरपंच के बारें में जिक्र हुआ था कि उसको डिसमिस किय गया है। उससे पता चलता है कि जो आगे विकटेमाइज़ेशन होने वाली है वह हमारी पार्टी के ऊपर कृपा होगी। गुड़गावं के समीप बादशाहपुर गांव में जो सरपंच है वह जनसंघ का उपप्रधान भी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा वह कल मेरे पास आया और कहने लगा कि उसकां इसी महीन की 9 तारीख को ससपैंड कर दिया गया। ओर जब मैने उसके ससपैशन आर्डर को पढा तो मुझे हैरानी हुई क्योंकि उसे ऊपर चार्ज लगाया गया कि उसस किसी 308 नम्बर को जो खसरे में दर्ज है वह बतौर सरपंच अपने पजैशन में लेने में कासिल रहा इस लिए पंचायत को नुक्सान पहुंचा है। उस नम्बर के बारमें मे सिविल कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि यह ग्राम सभा की प्रापर्टी है लेकिन फिर भी सरपंच ने कार्यवाही की ओर रैवेन्यू कोर्ट के अन्दर उसका कब्जा लेने की दरखास्त दी। उसकों नीलाम करने की समिति से परमिशन भी ली औ एक मैम्बर ने 17 रूपए गज के

हिसार से आफर थी दी लेकिन इन्होने कहां कि उस नम्बर को नीलाम किया जाए। इतना होने पर भी उसके ऊपर चार्ज यह लगाया गया कि वह इसका काब्जा नही ले सका जिसकों पंचायत को नुक्सान हुआ।

उपाध्यक्षाः आप का टाइम हो गया है।

मलिक मुख्तियार सिंहः तो फिर कहिए कि मै वैसे बिना कुछ कहे बैठ जाऊ। जब डिप्टी कमिश्नर से इस बारें में कहा गया तो वह कहता है कि मै या करूं हमारे ऊपर से दबाब पड़ गयाहै। और यह बैठे बैठे कहते है कि वह छोटी बातें है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी शुरू से ही यह पालिटीकल विडिक्टिवनैस का ग्लेयिरें मिसाल है (घंटी की आवाज)

आप तो घंटिया बजाने लगी अभी तो मैने बहुत कुछ बोलना है।

उपाध्यक्षाः देखिए सदन ने टाइम फिक्स किया है उसे मुताबिक चलूंगी। आप ज्यादा इनसिस्ट करते है तो आपको 5 मिनट और दिए देती हूं।

मलिक मुख्तियार सिंहः जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी चीफ मिनिस्टर साहिब ने और वजीर ऐग्रीकल्चर ने बड़े तमतराक से फरमाया कि हम ऐग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत कछ कर रहे है। लेकिन देखने मे यह आता है कि ऐग्रीकल्चर को तो इंडस्ट्री खाए जा रही है मै यह नही कहता कि

इंडस्ट्री को बढ़ावा न दिया जाए मगर मै गवर्नर ऐड्रैस के आधार पर इंडस्ट्री की एक मिसाल देना चाहता हूं। उसमें कहा गया था कि सोनीपत के अन्दर एक टाउनशिप बनाया जा रह है। और वहां पर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए साढ़े पांच हजार एकड़ जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। ओर 204 दफा के बहत एक नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। 25 गांव उसकी जद में आते है। जिससे 70/75 हजार के करीब पापुलेशन इनवालव होती हैं ओर जो यह लैड ऐक्वयर की जा रही है। वह बेहद फर्टाइल लैंड है जो यह जमीदारों से छीनना चाहते है। इंडस्ट्री बढाइए मगर एग्रीकल्चर की कास्ट परकयो। मुझे गोलडस्मिथ की कुछ लाइनों याद आती है।

"Princes may come and may fade:

A breath can mae them as a breath has made:

But a bold peasantry, their continuour pride.

When once destroed can never be suppoied."

अगर यह साढं पाच हजार मोस्ट फर्टाइल लैंड ले लें और फिर यह आशा करें कि पैदावार बढ़ती रहे तो यह कैसे हो सकता हैं इसलिए मै कहता हूं कि यह एग्रीकल्चर का भला नही करना चाहते।

इन्होने जो भट्ठे लगाए है वह भी फटइिल लैड्ज पर लगाए है। प्राइमेट ओनर जो भट्टा ठीक तरह से नही पकता

फर्टाइल लैंड पर ही पकेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐग्रीकल्चर को एनसैटिव देने के लिए कहते है कि हम इतना रूपया खर्च कर रहे। लेकिन मै बतानाचाहूंगा क किसान को जो कर्जा या सबडियी देने का प्रोसैस है वह इतना कम्पलीकेटिड है कि किसान को जितना रूप्या मिलना हेताहैं उसका मुश्किल से एक चौथाई उसे पास जाता है क्योंकि बीच में बहुत सा खर्चा हो जाता है जो दूसरें लोग खा जाते हैं नतीजा यह होता है कि किसान वह रूपया ऐग्रीकल्चर पर खच्र भी नही कर पाता क्योंकि उसकी और भी बहुत सी जरूरिसात होती है। इसलिए मै यह कहूंगा कि जो इस तरह का पेचीदा प्रौसैस है उसकों आसान बनाना चाहिए ताकि किसान को पूरी रकम मिल सकें ओर वह उसे एग्रीकल्चर पर खर्च कर सकें डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल जब मै रेल में ट्रैवल कर रहा था तो वहां एक फैलों पेसेंजर ने बड़ा इंट्रस्टिग सवाल पूछा

उपाध्यक्षाः आप का टाइम हो चुका है।

मलिक मुख्तियार सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै कोई फजूल की बकवास तो नही कर रहा मैने तो बात अपने मतलब की कहनी है।

उपाध्यक्षाः आप अपनी मर्जी की बात कहें लेकिन आप का समय हो चुका है।

मलिक मुख्तियार सिंहः टाइम के ऊपर तो किसी की कोई मोहन नही लगी हुई इतनी देर में तो मै बात कह कर बैठ

भी जाता। आप की कोई पोलिटीकल कुर्सी तो नही है कि आप के ऊपर कोई ज्यादा दबाव पड़ गया है।

उपाध्यक्षाः नही, मै किसी का लिहाज तो नही करती।

मलिक मुख्तियार सिंहः मै अर्ज कर रहा थाकि उस आदमी ने पूछा कि एक रेल इधर जाती है चालीस मील और दूसरी उधर जाती है। उसका फासला 42 मील हा है तो बताओं मि मेरी उमर कितनी हैं तो सब हैरान हु कि यह कैसे बताई जा सकती है। लेकिन एक आदमी वहां और बैठा हुआ था वह कहने लागा कि मै बताता हूं आप की उमर 44 साल की है। तो उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक बताया है लेकिन यह बता कि हिसाब कैसे लगाया। इस पर उसने बताया कि मेरा एक दोस्त नीम पागल है उस की उमर 22 साल है है और तुम क्यों पूरे पालग हो इसलिए तुम्हारी 44 साल मैने बता दी। तो यह जो उधर बैठे हुए है उनकी ठीक वैसी हालत हैं। हमें पता है कि यह किसानों परटैक्स लगाएंगे, आब्याना बढ़ा रह है। और यह सब कुछ एक किसान के बेटे बसी लाल के हाथें से यह सब कुछ करवा के उसको कार्नर करना चाहते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, दरख्त वैसे तो नही कटता था, उसके लिए एक कुल्हाडी लोहे और फौलाद की बनी लेकिन उसे अन्दर दस्ता लकड़ी का डाला गया यानी लकड़ी की मदद लेकर लकड़ी को काटा गया है। तो ठीक इसी तरह किसान को किसान के हाथों से यह कटवाना चाहते है। यह कहते है कि किसान पर इन्कम टैक्स लगाओं। सूबेदार प्रभु सिंह जो चांद राम

से लड़ता रहता है, अब पता नही कहा चला गयाहै, 20 साल से इनने उनको बहका रखा है, कभी इन्हाने उन को मन्दिर में चढ़ा दिय, कभी कुएं पर चढ़ा दिया और कभी किसानों से लड़ा दिया। मै उन्हें कहता हूं कि तुम्हारी पेशैस अब खत्म हो चुकी है, क्यों झोअे के ीनीच बाल्टी रखे बैठे हो, उसके नीचे से दूध कहां से निकलेगा। कांग्रेस ने 20 साल तक आपकों बहकाया कि आपको जमीन दी जाएगी औश्र आपस में हरिजन और किसान का लड़ाया लेकिन इस 20 साल के अर्से में आप का इनफीरियर इवैक्युइ लैंड भी नही मि पाई। आप इनमें कोई उम्मीद मत रखे आप को जमीन नही दी जाएगी चाहे कितना ही इनके साथ लगे रहो, इतना कह कर मै बैठ जाता हूं।

श्री रूप लाल मेहता (पलवल): डिप्टी स्पीकरक साहिबा, मै ने अपनी कट मोशनज डिमांड नम्बर 9 और 22 पर रखी है। इसमें कोई शक नही कि हमारा हरियाणा प्रांत अभी थोड़ी सी उम्र का है। लेकिन इसमे जो मुलाजमीन हमारे हिस्से में आए है वही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह चला सकते हे। हम करोड़ों रूपये एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते है। और उसके बदले में चाहते है कि हमें साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन मिले ताकि गरीबों की सुनवाई हो सके। लेकिन आज मै देख रहा हूं कि हम इतनी हैवी एडमिनिस्ट्रेशन बनाते जा रहे है कि हमारे प्रांत को जिसे अभी थोड़ा अर्सा बने को हुआ है उसक बोझ उठाना मुश्किल हैं इस सरकार को अभी बने सिर्फ दो महीने हुए है इसलिए इसके

कामों का अगले साल सही जायजा लगेगाकि अच्दे है या बुर है। लेकिन सर्विसिज अगर चाहे तो सरकार को अच्छा बना सकती है औरर चाहें तो बुरा है। हमें आजादी मिले 20 साल से ज्यादा हो गए है। हम चाहते थे कि यहां राम राज्य हो और लोगों को 20, 20 दिन इन्तजार करनी पड़ती है, करप्शन बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके इलावा कुछसरकार के डिवेल्पमेंट के महकमें है जिनका लोगों को लाभ होना चाहिए था ओर ख्याल थाकि सूबे में खुशहाली आएगी लेकिन जो ब्लाक समितियों ओर पंचायत समितियों में विकास के लिए आफीशियल्ज लगाए हुए है। वह किसानों को मौके पर बीज तक भी नही दे सकते। मै आपे हल्के में देखता हूं कि लोगों को छोटे छोटे कामें के लिए हुित हैरान होना पड़ता है। निचले दर्जे के मुलाजमों को जब तक नही सुधारा जाएगा उतनी देर तक हमारे सूबे की भलाई नही हो सकती। राम राजय कागजों में तो है लेकिन हकीकत में कोई राम राज्य नही बना जिसे लाने के लिए हम जेलों में जाते रहे ओर हमारे महान नेता महात्मा गांधी जी ने इतनी सैक्रीफाइसिज की। इसके इलावा मै गुजारिश करूंगा कि जो टाप हैवली एडमिनिस्ट्रशन है इसको कम किया जाए। हर महकमा में दरजनों बड़े बड़े अफसर लगे हुए है। उनकी बड़ी बड़ी तनखहे है और वहबेकार बैठे रहते है। इनका बजाए सैक्रेटेरियेट है और वहां पर जो काम एरियर में पड़ा रहता है वह नही रहेगा ओर लोगों की सहूलियत हो जाएगी। फिर जो सोशल वैलफेयर डिपार्टमैट है और पब्लिक रीलेशन डिपार्टमैंट है। इनको एक जगह करके मर्ज कर दिया जाए और डिवेल्पमेंट

डिपार्टमैंट के नीचे कर दिया जाए। इससे सरकार का खर्च घट जाएगा और लोगों पर से टैक्सों का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके साथ मै कहना चाहता हूं कि यह तो विजीलेंस डिपार्टमेंट है यह खमखाह का सरकार के ऊपर खर्च पड़ा हुआ हैं इसका काम सिर्फ यही है कि इसके अफसर मामजली चपड़ायिों और क्लकों को ही पकड़ते है और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने लाखों रूपये रिष्वत के खा कर कोठियों बनाई हुए है उन्हे पूछते नही है कि यह इतना रूपया उन के पास कहा से आया है। यह महकमा कोई काम नही करता हौर ऐस.पी., डी.ऐस.पी. और इन्स्पैक्अर बगैरह जितने अफसर है वहा कोई काम नही करते सिवाए इसके कि किसी गरीब छोटे से मुलाजम को पकड़ लिया और उसकी इनक्वायरी में पड़े रहते हैं मै समझता हूं कि इस महकमा की कोई जरूरत नही है और अगर एक ही सी.आई.डी. का महकमा इस काम को करे तो काम ही अच्छा हो सकत है। और सरकार का पैसा भी जो इतना बड़े बड़े अफसरों और स्टाफ पर खर्च हाता है वह सारा बच सकता है। इसी तरह पब्लिक रीलेशन डिपार्टमैंट पर खाहमखाह इतना रूपया खर्च किया जा रहा हैं कई जिलों में फील्ड पब्लिसिटी अफसर रखे हुए हुए है जो पांच पांच सौ रूपया तनखाह लेते है और काम उने पास एक पैसे का भी नही है सिर्फ नैनशन ही ले रहे है। मै समझता हूं कि अगरइसकों तोड़ कर इसे डिवेल्पमेंट के महकमें के अंडर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा और इससे सरकार को खर्च में काफी बचत हो जाएगी। यह जो बजट में आठ करोड़ रूपए का घाटा है इसे आप इस तरह पूरा कर

सकते है। लेकिन अगरआप अैक्स लगा कर जनतासे यह रूपया पूरा करने की कोशिश करेंगे तो जनता हमें कोसेगी और इस चीज को बरदाशत नही करेगी। इसलिए यह जो ऐसे ऐसे फजूल के महकमें है आप इनकों तोड़ कर अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च को घआ कर रूपया बचायें और जनता पर 'टैक्सों का' और बोझ डालने की कोशिश न करें। मै हरियाणा की इस नेक देवी को जो हमारी वित्त मंत्री है। इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होने हरियाणा की गरीब जनता पर कोई नया टैक्स नही लगाया।

दूसरी कट मोशन मै ने इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट के बारें में दी है और वह इसलिए दी है कि सरकार इस महकमा के लिये काफी रूपया देती है लेकिन यह महकमा इस बात को नही देखता कि इन्डस्ट्री कहां पर लगानी चाहिए और कौनसे इलाके इगनोर हो गए है। और यह महकमा पसमांदा इलाकों का कोई ख्याल नही करता। मेरा पलवल का इलाका निहायत पसमांदा है लेकिन इस इलाका में इंडस्ट्री लगाने के बारे में कभी नही सोचा गया। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों मुझे कहा करते थे कि Induce somebody and I will give him all the facilities." उनके बाद जितनी सरकारे आई इन मे से किसी ने पलवल में इन्डस्ट्री लगाने के बारे में ध्यान नही दिया हालांकि मै हर सैशन में इसके लिये आवाज उठाता आ रहा हूं। मै अपनी इस सरकार से कहना चाहता हूं कि बलभगढ़ से होडल ती जो जी.टी. रो के साथ साथ जो 33 मील का इलाका है वहां पर इन्डस्ट्रियल ऐसटेट बनाई जाए। अगर

आप ऐसा करेंगे तो लोग बड़ी खुशी से कारखाने लगाएंगे क्योंकि वहां पर सारी सहूलितें है। जो जी.टी. रोड है, रेलवे के साधन है और बाकी सारी फेसिलेटीज है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरे इलाका के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त हमारे पलवल में कोई दस हजार पंजाबी भाई बेरोजगार बैठे है। कोई लकड़ियां बेच कर गुजारा करता है तो कोई चने बेच कर अपने बाल–बच्चों का पेट पालता है। पार्टीशन हुए इतने साल हो गए है लेकिन अभी इस जगह कोई इंइस्ट्री नही लगाई गई कि जिससे इन लोगों को रेाजगार मिले। अगर कोई कारखाना लगाते है तो फरीदाबा में ही लगाते है औरजो लोग देहली में बैठे है उनके लिये ही लगाते है। जितने कारखने वहां लगे है उनके मालिक देहली में रहते है और सारी आमदनी जो स्टेट में रहनी चाहिए वह सारी देहली चली जाती है। उने कारखाने तो फरीदाबाद में है लेकिन हैड आफिस उनके देहली में है जिससे सारा रैवेन्यू देहली चला जाता है। इसलिए मै सरकार से निवेदन करता हूं कि बलभगढ़ से होडल तक जो 33 मील का टुकडा है वहां पर इंडस्ट्रियल ऐस्टेट कायम करें ताकि वहां के लोग भी तरक्की कर सकें। पलवल एक तारीखी कसबा है जाहं कि महात्मा गांधी जी ने जंगे आजादी का बिगुल बजाया था लेकिन आज उस कस्बे की हालत यह ळै कि वहां लोगों के पास रोटी कमाने के लिए साधन नही है। मै हैरान हूं कि मेरे सवाल के जवाब में चीफ मिनिस्अर साहब नेकैसे कह दिया कि वहां पलवल में कोई इंडस्ट्रियल ऐसेटे नही बनेगी और उस इलाके के सथ ऐसा सलूक करने की क्या वजअ है जो उसे

इगनोर किया जा रहा है। मै उसके इस जवाब से बहुत ओफैड हुआ हूं। उस इलाका से कांग्रेस को हमेशा बहुमत मिलता हैं क्या वह यह चाहते है कि वहां के लोगा कांग्रेस को छोड़ दें तो वह ऐसी बातें करते है। इसी तरह अभी पी.डब्लयू.डी मिनिस्टर साहन ने कह दिया कि वहां पलवल में घोड़ी तक वाली सड़क नही बनन सकती। क्या इनकों यह पता नही कि लोगों को मंडी में माल लाने के लिये कोई साधन नही है। इसलिए उन्हें इस सड़क की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके बगैर लोगों का गुजारा भी नही हो सकता। पलवल की इस वक्त 15 हजार से बढ़कर 40 हजार आबादी हो गई है लेकिन वहां हालत यह है कि वहां हस्पताल में कोइ दवाई ही नही है। कमेटभ चार सौ रूपया उसको दवाईयों के लिये देती है। आप अंदाजा लगाएं कि इस रकम से क्या दवाइयां आएंगी। सरकार को चाहिए कि उस हस्पताल को आपने हाथ में लो और ज्यादा रूपया वहां दवाइयों के लिए दिया जाए। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का यह हाल है जरायम की तादाद बढ़ती जा रही है और चोरिया और कत्ल बढ़ते जा रहे है। मेरे पास पिछले सालों के कुछ आंकड़े है जो मै आपे नोटिस में लाना चाहता हूं। 1965 में 4,467, 1966 में 4,534 और 1967 में 7,043 जरायम हुए। आप देख सकते है कि हर साल इनकी तादार बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों पलवल में एक कांग्रेस का वर्कर कत्ल हो गया लेकिन उसे ट्रेस करने में इलाका की पुलिस बड़ी सुस्ती से काम ले रही है और अभी इस बारें में कोई ठोस कार्यवाही नही की गई। इसी

तरह सराए खटेला मे ंएक ट्रक ड्राईवर को कत्ल कर दिया गया लेकिन पुलिस आज तक मुलज़म को नही पकड़ सकी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि अगर सरकार ने जरा भी ढील की तो लोगो ने जान ओर माल को भारी खतरा पैदा हो जासएगा। अभी पिछले दिनों मेरे जिलने पलवल मेंचार केस कत्ल के हुए है। इतनी धांधली मची हुई जिसका कोई ठिकाना ही नही है। अगर लोगौ के हौसले इस तरह बढ़ते रहे लोग एक दूसरे के खून के प्यास बनते रहे तो ला–एण्ड आर्डर की हालत बहुत खरबा हो जायेगी। इसके इलावा डिस्ट्रिक्व लैवल पर पटवारी किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नही करते। किसान जब तहसील मे। जाता है तो उसकी नुक्ताचीनी की जाती है। इस तरह जनता के साथ लैवल पर मुलाजमों की तबदीलियों करें ताकि उन्हें यह अहसास हो जाये कि किसी इलके में जाकर जनता के साथ कैसा व्यवहारकरना चाहिए। आप देखें कि अगर कोई आदमी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो कोई दर्ज नही करता। जो मजबूत लोग है वे अपना हरकाम करवा लेते है। लेकिन जहां तक हरिजन या दूसरो गरीब लोगों का ताल्लुक है उनकी कोई बात नही सुनता और पुलिस भी रक्षा नही करती।

उपाध्यक्षाः मेहता साहब, आपका टाइम हे गया है, आप बैठ जाए। आपकों तो वैसे ही ज्यादा टाइम मिल गया है।

श्री रूप लाल मेहता: थोड़ा सा टाइम और दे दें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे जज़बातों से जाहिर है कि मै अपने इलाकों के लोगों के दुखो को सदन के सामने रखूं। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री साहब मेरे इलाके की तरफ ध्यान देगें। मै कहना चाहता हूं कि पी.डबल्यू.डी. ओर स्वास्थ्य के महकमों के लिए और रूपया दिया जाना चाहिए। अगर आपके पास नही है तो लाओं बजट मेरे पास दे दो, मै चीर फाड़ करके रूपयादे देता हूं जो बड़े बड़े सफेद हाथी बैठे है वे मुलाजमों को तंग करते है, उन्हें सस्पेंड करते है और केस चलाते है उन्हें हटा दिया जाये तो बाकी मुलाजमों को सबक मिलेगा।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे सामाने जो डिमांडज आई इनके बारें में मै कुछ कहना चाहता हूं। आजादी मिलने के बाद अगर हिन्दुस्तान ने किसी चीज में तरक्की की है वह करप्शन ओर दूसरी टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन का जहां तक ताल्लुक है, मै समझता हूं कि इसके लिए न तो प्रैजेंट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है और न पहिले वाली मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। यह तो शुरू से ही बढऋती जा रही है। इसमें किसी विशेश सरकार की जिम्मेदारी नही है। इसका इलाज भी कोई नही है न ही कोई करसकता है औ न ही हो सकता है। अब टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने का सवाल है। इस दिशा में अगर सरकार कुछ सख्त कदम उठाये तो कामयाबी हासिल हो सकती है। जहां तक सैक्रेटेरिएट का ताल्लुक

है। इसमें काफी टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मिनिस्टर साहबान थोड़ी सी हिम्मद से काम लें तो मुलजामों की संख्या को घटाया जा सकता है। जहां तक सैक्रेटेरिएट की वकिग का ताल्लुक है वहां तो क्लर्क राज है। जो क्लर्क नोट लिखता है उस पर एसिस्टेंट, सुपरिटैडैट, एसिस्टेंट सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी, ज्वायंट सैक्रेटरी ओर सैक्रेटरी सबके सब अपना अपना नाम काट कर दस्तखत कर देते है और वह केस उसी तरह मिनिस्ट साहब के पास चला जाता है आगे मिनिस्टर साहब भी वैसे ही दस्तखत करके वापिस भेज देते है। ये जितने भी ऊपर के आफिसर है ये दस्तखत करने के सिवाये और कुछ नही करते। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस काम के लिए क्लर्क, सुपरिटैडेंट और डिप्टी सैक्रेटरी ही काफी है। इनके इलावा बाकी की जितनी भी पोस्टें है उनकों खत्म किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हरियाणा के फाइनेंशल कमिश्नर की कई ऐसी पोस्टे है जिनकों खत्म किया जा सकताहैं इस सम्बन्ध में मैने बतरा साहब से बातचीज की उन्होने कहा कि हम कोशिशकररहे हे। अगर यह काम ठीक रहातो मै समझता हूं कि फाइर्नेशन कमिश्नर की एक पोस्ट हरियाणा के एिल काफी है, बाकी पोस्टे अबालिश कर दी जानी चाहिएं। इसके इलावा पुलिस डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी बहुत हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। मुझे श्री रूप लाल मेहता जी की स्पीच ठीक रतह से सुनाई नही दी, कुछ थोड़े से लफ़ज मेरी समझ में ओय

है। इन्होने भी विजिलेंस डिपार्टमेंट का जिक्र किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने के लिए सैक्रेटरिएट लैवल और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कदम उठाये।

दूसरी डिमांड जो एग्रीकल्चर की है, उसे बारे में अर्ज करना चाहता हूं। दरअसल बजट इस किस्म का बना हुआ है, इसकों नये मेम्बर तो क्या पुराने मेम्बर भी नही समझ सकते है। मैने पिछले वित्त मंत्री श्री मूल चन्द जी से बजट के बारें मै समझने की कोशिश की थी। उन्होने कहा था कि यह बजट बनाना सैक्रेटेरिएट में बैठे हुए अफसरों को काम है, मिनिस्टरों की समझ मे नही आ सकता। यह ठीक बात है।

वित्त मंत्रीः मेरे पास आ जाइए, मै आपकों बतला देती हूं।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः आप माफ करना, मेरे ख्याल आप लोगों के बारें में मुख्तलिफ है। मै श्री मूल चन्द जैन को आपके मुकाबिले में बहुत काबिल समझता हूं। (विघ्न) मै कह रहा था कि इस बजट में बहुत सी चीजें पेश की है जो हरियाणा के अन्दर एग्जिस्ट ही नही करती। बजट में एक ''आइटम है आयल सीड एक्सट्रैक्शन स्कीम'' जो बजट के 263 पृश्ठ परहै। मुझे तो पता नही कि इसके बारे में कोई काम होता भी है या नही, स्टेट लैवल पर कोई अफसर होगा जो इस स्कीम पर बकाम करता

होगा। लेकिन मै जींद के बारें में दावे से कह सकता हूं कि वहां पर इस स्कीम के तहत कोई अफसर फील्ड में काम नही करता। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जहां तक फील्ड वर्किग का सवाल है वह बिल्कुल सिफर है। कोई भी अफसर ऐसा नही है जो लोगों को समझाये, कोई अच्छी बात बताये और उनका नुक्सान होने से बचाये। जो केन कमिश्नर है वे मिल एरिजयाज के अन्छर ही रहते है दूसरी जगहों पर नही जाते। मिल एरियाज क इलावा दूसरी जगहों पर भी बहुत या गन्ना पैदा होता है, वहां भी केन कमिश्नर को जाना चाहिए। पिछले साल देखा गया है कि जिस जमींदार ने आठ आठ दस दस एकड़ तक गन्ना लगाया हुआ था जिस वक्त गन्ना पीड़ने का वक्त आया तो उसका सारा गन्ना सूख गया। किसी अधिकारी ने जाकर यह नही देखा कि गन्ना सूखने की क्या वजह है इसलिए केन डिपार्टमेंट को चाहिए कि जिन एरियाज के अन्दर मिले है उनको छोड़कर बाकी एरियाज में भी काम करें ओर लोगों की तकलीफ को देखे।

अब में कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में मे कहना चाहता हूं अगर सही मायनों में इस डिपार्टमेंट का नाम रखें तो यह करप्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। इसके अन्दर जितनी धांधली मची हुई है उतनी कही नही है। इस बात को कोई हिसाब किताब नही है। कि कितना माल आया और कितना गया। जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज बनी हुई है। उनकी मारफ्त तमाम चीजें बेची जाती है।

इस तरह इस डिपार्टमेंट में बहुत सोसायटीयों शामिल है। मेरे हल्का सफीदों में भी एक कोआप्रेटिव सोसायटी है। वैसे हर आदमी को उसे कोटे के मुताबिक चीनी दी जाती है अगर शहरी हो तो शहर के हिसाब से दी जाती है और अगर देहाती हो तो उसे देहात के हिसाबा से दी जाती है। लेकिन सफीदों में जों सोसायटी है। वहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को दस बोरी दे देते है, किसी को पांच बोरी दे देते है। इन्स्पैक्अर साहब को इस बात का पता होता है। वह भी सोसायटियों वालेां से मिला होता है इसलिए वह उस केस को दबा देता है। इसलिए मै अर्ज़ करूगा कि कोओप्रेटिव डिपार्टमेंट में इस तरह की जो धांधली है, उसे जरूर बन्द रकें और जितनी ज्यादा से ज्यादा करप्शन दूर हो सकती है, दूर करें। कोआप्रेटिव मूवमेंट तो रूस में भी फेल हो चुकी है जहां कम्युनिस्ट राज है। हमारे यहां यह चलने का नही। वैसे यह नेहरू जी की दे है और इसे आप चलाना ही चाहें तो चलाते रहें, परन्तु इसका कोई फायदा नही है।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट के बारें में अर्ज करूंगा कि इस विभाग के डिपुओं और मार्किट में बेची जानी वाली चीजों के रेटस में बड़ा अन्तर होता है। इनकी चीजों का बड़ा हाई रेट होता है जबकि उसी किस्म की चीज बाजार में सस्ती मिल जाती है। यदि सरकार को मेरा सुझाव है कि एक तो सरकार डिपार्टमेंट के लिए भी उसे कम्पीटीटिव

रेटस पर चीजें खरीदनी चाहिए और दूसरे इन डिपुओं की वर्किंग में जितना सुधार किया जा सकता हो किया जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट में सरकार ने करनाल के एक मधुबन दरी एंडखेस मंकिंग सैन्टर को ग्रान्ट देने के लिए कुछ पैसा रखा है। मै ने तो इस नाम का सैन्टर वहां कभी देखा नही। मैने वहां के मेम्बर साहिबान से भी बातचीत की परन्तु उन्हें भी इसका पता नही। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब कोई चीज एगजिस्ट ही नही करती तो पता नही क्यों उसके लिए पैसा रखा गया है। मेरे ख्याल में कपूर एंड सन्ज या जो कोई भी इनके है, इनसे इसे बनवाना चाहते है वरना प्राइवेट इन्स्टीच्यूशनज के गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है। इस तरह की बजट में और भी बहुत सी चीजें है मगर समय के अभाव के कारण न तो उन्हें हम जल्दी से पढ़ ही पाए है और सच कहूं तो बहुत कछ बातें समय के अभाव के कारण न तो उन्हें हम जल्दी से पढ़ ही पाए है और सच कहूं तो बहुत कुछ बातें समझ मे भी नही आई। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा बहन ओमप्रभा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि पैसे को ऐसी फजूल की चीजों पर खर्च करने की बजाय दूसरे विकास के कामों पर खर्च किया जाना चाहिए।

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मै आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझ सदन के सामने अपने विचार पेश करने का मौका दिया है। बजट के ऊपर जनरल बहस बहुत लम्बी चौड़ी हुई और हमारे अपोजीशन ग्रुप के

जो लीटर है उनके भाषण को भी मैने बड़े गौर से सुना। ज्यादातर क्रिटिसिज़म पोलिटिकल टाईप का था बजट में कहां रूपया ज्यादा रखा गयाहै और कहां कम रखा गया है इसके बारमें मैं कोई खास बात मैने नही सुनी। एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा जोर दिया गया कि एग्रीकल्चर को निगलैक्टर किया जाता है, किसानों को निगलैक्ट किया जाता है। हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बड़ स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि अन्दाज 73 परसैन्ट बजट का एक्सपैन्डीचर जा है वह एग्रीकल्चर, इरीगेशन और पावर पर होता है। अगर इतना होने पर भी मेरे दोस्त में नाराजगी है तब तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै समझता हूं कि यदि यह पैसा और ज्यादा जाने की जरूरत नही, मै खास तौर पर एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्री में कुछ भी नही किया गया। वार आइम में और प्री–वार–टाइम में मैने देखा कि कपास नारनौल के हल्के में पैदा हुआ करती थी, नारनौल में बाकायदा एक जिनंग एंड प्रैसिग फैक्टरी चलती थी लेकिन अब वह बंद है। इसी तरह से वहां वार आइम में एक वूलन फैक्टरी थी जो कि आर्मी को ऊनी कम्बल सप्लाई करती थी, ए. जी.जी. लाहौर से उसे देखने वहां आए थे औरउसने उसकी बड़ी सराहना की थी लेकिन आज उस फैक्टरी का वहा नामोनिशाननही। तो यह तरक्की हुई, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे यहा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, महेन्द्रगढ़ का पशु बहुत मशहूर है। वहां से भैसे और गाये भारी संख्या में दूसरे राज्यों और

जगहों को जाती है। वहां से घी ने मिल्टरी डिपार्टमैन्ट से फर्स्ट क्लास का दर्जा हासिल किया हुआ है अज्ञै सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। खुर्जा की मंडी के बाद नारनौल के घी की तारीफ होती है। पटियाला राज्यके समय में बनस्पति घी वहां लोग नही ला सकते थे। लोगों प्योर घी खाने को मिलता था। युरोपियन लोग भी ज्यादातर नारनौल करते थे लेकिन डऋे अफसोस की बात है कि आजादी के बाद वहां के कैटल की इम्प्रूवमैन्ट के लिए बजट के अन्दर हमने कभी प्रोवीजन नही देखा। मै पिछली बातों के लिए इस सरकार को तो ब्लेम नही करता लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चीजों की चीजों की तरफ हमारी वर्तमान सरकार की तवज्जुह होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि मेजर अमीर सिंह जी ने जिक्र किया, बोरिग मशीन की सप्लाई के लिए एक केस मूल किया था, परन्तु अभी तक उसका कुछ नही बना। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब वहां लोग कुआं खोदते है तो बीच मं चट्टाने आ जाती है। और यहां तक कि पहाड़ आ जाते है जिनकों मशीन के बगैर तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मामूली बोरिग और ड्रिलिग मशीन से भी काम नही चलता। और जिलों में जबकि एक दो हजार रूपये से कुआं खोदने का काम चल जाता है वहां आठ–दस हजार रूप्ये खर्च करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से खोदा जाता है। मैने कई दफा कन्सर्न्ड अफसरों की, यहां त कि मिस्टरफलैचर की तवज्जुह भी इस तरफ दिलाई थी और उन्होने

कुछ शुरू कर दिया था। मगर बज वे जमाने तो गए। मैने जब भी कईयों से कहा कि जिस तरीके से मशीन से खेतड़ी के अन्दर गवर्नकेंट कोपर ट्यूबवैल लगा रखे है और आर्टिफिशियल नहर बना रखी है, उस तरीके की बोरिंग मशीन हमारे इलाके के लिए दी जानी चाहिए। (एक सदस्य विजिटर गैलरी में बैइे हुए एक व्यक्ति से बातचीत करने लगे)।

(Noise and interruption)

Deputy Speaker: Order pldase. Honourable Members should not talk with the people in the Gallery.

श्री रामसरन चन्द मित्तलः तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै अर्ज कर रहा था कि एक बड़ी स्ट्रांग बोरिग मशीन के वहां दिए जाने की बड़ी जरूरत है ताकि लोग कुएं खोदकर जमीन की सिंचाई कर सकें क्योंकि दादरी के इलाके के सिवाय जहों एक नही है, यारी की सारी जमीन बारानी है। पंजाब गवर्नमेंट तो कुएं खोदने के लिए लोगों को तीन हजार रूपए कर्जा दिया करती थी। बाकी पांच–सात हजार रूपये लोग अपने पास से लगा लिया गरते थे। ऐसा भी अगर साथ साथ हमारी गवर्नमेंट कर सके तो और अच्छी बात होगी मगर यदि अभी न हो सकें तो मै बड़ी नम्रता के साथ अपील रूंगो, अर्ज करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि महेन्द्रगढ़ के लिए एक बोरिंग मशीन का जल्दी से जल्दी इन्तजाम किया जाना चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर सहिबा, आप इलाकें में जाकर किसी

से पूछे कि भाई तुमको क्या चाहिए, तो प्रत्येक अपदमी के मुंह से आप सुनेगी कि बोरिग मशीन चाहिए।

पैप्सू के जमाने में डिप्टी स्पीकरसाहिबा, वहा कुछ बांध लगाए गए थे। एक बांध अमरपुर चौरासी में था। उस समय मिस्टर मल्होत्रा जो इंजीनियर थे उन्होने कहा था कि इस बांध की युटिलिटी का पता आपकों पांच सात वर्ष के बाद लगेगा और वाक्या ही पांव सात साल के पांच सात मील के एरिया में कुआं का वाटर लेवल इतना ऊंचा हो गया कि खेती का पानी देना बड़ा आसान हो गया। लोगों को इससे बड़ा फायदा पहुंचा है। इसलिए सरकार से मैं अर्ज करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बांध वहां बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को पानी की सहुलियत मिल सकें। लोग इसके लिए सुझाव देने के लिए तैयार है। मै भी कई जगहों के नाम बता सकता हूं। दूहान नदी के ऊपर हमीदपुर गांव के पास एक बांध बना था। सरदार प्रताप सिंह कैरों, डाक्टर उप्पल और मै वहां गए भी थे। वहां का पानी ब्रैकिा था। वह बांध कई सालों तक बनात रहा टूटता रहा और अब व टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ हैं उसमें दिक्कत यह है कि जितनी बार भी वहां बांध लगया गया उतनी बार ही वह पहले फलों में ही बहता रहा। इसके लिए भी मेरी सरकार से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा प्रार्थना है कि टैक्नीकल राय लेकर जिस किसी भी ढंग से यह बांध बन सकता हो इसे बनाया जाना चाहिए ताकि लोग इससे भी फायदा उठा सकें।

खेती के लिए दूसरा हल इलैक्ट्रीसिटी है। पानी के साधनों के लिए मास स्केल पर रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन की मांग है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी मिले और लोगों की पानी की किल्लत हटे। जो अनाज हमे दूसरे डिस्ट्रक्ट से मंगाना पड़ना है और हमारे जिले में अनजा की जो किल्लत है अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिजली पहुंचा दे और टयूबवैलों के लिए बिजली दे तो हमें अनाज दूसरे जिलों से मंगाना ही न पड़े और यहां से दूसरे जिलों को हम अनाज भेजें।हमारे यहां सरसों अच्छे किस्म की होती है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। हमारे यहां की सरसो बाहर जाती है, हमारे यहां का तेल बाहर दूसरी जगहों पर जाता है। इसलिए मै अर्ज करूंगा कि हमारे यहां एग्रीकल्चर की डिवल्पमेंट की तरफ खास ध्यान दियाा जाये।

अब इंडस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूं हमारे यहां आबादी बढ़ रही है, खेती पर काफी प्रैशर हो गयाहै इस लिए दूसरा तरक्की का तरीका इंडस्ट्री को इन्क्रीज करने का है। दूसरे कन्टरीज अमेरिका वगैरा मैं जहांा फूट ग्रेनज और एग्रीकल्चर पर ज्यादर जोर देते है तो साथ ही इंडस्ट्री पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है हमारे हरियाणे के लोगा काफी तादाद में सूबों मुं जाकर व्यापार कर रहे है। उन्होने अपनी फैक्टरीज कलकत्ता बम्बई, हैदराबाद दक्कन, कानपुर वगैरा में लगायी हुई है। ओर डनहोने वहां पर अच्छा नाम पैदा यिका है। क्या वजह है कि यहां के लेाग यहां पर हरियाणे में इंडस्ट्री नही लगाते? बटाला फगवाड़ा

वहां पर जहां ने कोयला है, न लोहा है लेकिन वहां पर तरह तरह के इन्जीनिरिंग इंडस्ट्री है। मै आपने यहां की बताता हूं नारनौल में इंडस्ट्री एस्टेट बनायी गयी, काफी रूपया खर्च किया गया, लेकिन इस वक्त वह तमाम खाली पड़ी हुई है। कुछ साल पहले जब मै सोनीपत गया था तो वहां पर जा कर मैने देखा वहां पर भी यही शिकायत है कि कोई भी लोकन आदमी यहां फैक्टरी नही लगाये हुए है। मै इस बात की तरफ खास तवज्जुह दिलाना चाहिता हूं कि इंडस्ट्री कि डिवैल्पमै।ट के लिए यहां परकाफी गुंजाइश है। हमारे हरियाणा के लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। कुछ एक मित्रों ने यहां शिकायत की कि पिग आयरन प्लांट हिसार में लगाना चाहिए। मै तो चाहता हूं कि जरूर लगे लकिन उन लोगो से पूछा जाय कि हिसार में किस लिए लग, क्या वहां पर कोई लोहे की कान है, कोई कोयले की कान है? तमाम लोहे की काने मेरे हल्के में है। सारे हरियाणे में सिर्फ मेरी कान्स्टीच्यून्सी महेन्दगढ़ के जिस जिले में कान है लेकिन वहां पिग आयरन प्लांट नही लागते वहां परकोयला चीप आता है, बंगाल, बिहार से बमुबाले हिसार के। उस वक्त पंजाब में यह स्कीम बनायी गयी थ। पानी यहां नारनौल से काफी सप्ताई कर सकते है ओर पानी भ यहां सस्ता पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके से हमारे इलाके से बाहर नही लगना चाहिए। आज आप इस बात पर गौर करें और स्कीम खत्म नही होने देनी चाहिए लेकिन मेरी राय में यह पिग आयरन प्लांट हमारे जो बैकवर्ड इलाके है और ईश्वर ने वहां काने दी हुई है वहां लगाना चाहिए। जब ज्वायंट पंजाब था उस वक्त

से पिग आयरन प्लांट की बात चल रही है ओर मेरी कान्सटीच्यून्सी में लगाने की बात थी। वहां का कच्चा लोहा जापान और चैकोस्लोवकिया एक्सपोर्ट होता था, जब वह इसे काम में ले सकते है। तो नारनौल में भी यह पिग आयरन प्लांट कामयाब हो सकता है तो मै ज्यादा न कहता हुआ इनता ही आर्ज करूंगा कि (As this stge Shri Daya Krishan a mamber of the Panel of Charimen occupied the Chair) चेयरमैन साहब, जब बजट में मिनरल्ज की एक्सप्लोरेशन के लिए लाखों रूपए प्रोवाइड किये जाते है महेन्द्रगढ़ और गुडगांव के लिए तो इन मिनरल्ज, जो भी वहां पर इस इलाकें में होते है उनको काम में लाया जाये, उनसे फायदा उठाया जाये। मिनरल्ज की डिवेल्पमेंट स्कीम साइंटिफिक तरीके से तैयार होनी चाहिए, जिससे वहां के लोगों को फायदा पहुंचे। वहां परतो यह तमाम चीजें राआर्गेनाइज होनी चाहिये जो भी स्कीमें है उनसे फायदा पहुंचे और वे स्कीमें हमं एडाप्ट करनी चाहिए।

अब मै एग्रीकल्चर के बारें में अर्ज करना चाहता हूं। रोज–ब–रोज मकेनाइजड एग्रीकल्चर बढ़ रही है। आज हमारी नयी जनरेशन के लिए स्कूलों में एग्रीकल्चर का सब्लेक्ट रखा जाना चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान और रूझान इस तरफ हो। मै यह नही कहता कि से सब लोग एग्रीकल्पर में जाये लकिन उससे इम्प्रूवड तरीके एग्रीकल्चर में एडाप्ट करने मे उनका रूझान हो

जायेगा। जितनी भी खेती के लिए इम्पोटेंट बातें है उनकों आसानी से इम्पलीमेंट कर सकेंगें।

अब, चेयरमैन साहब, मै डेरी के मुताल्लिक कुछ बातें कहना चाहता हूं। डेरी के लिए रूपयाऔर जिलों ाके दिया गयाहै वहां हमारे जिले में कैटेल बड़े अच्छे है काफी वहां स दूध मिल सकता है। अगर हमारी सरकार यह मिल्क प्लांट वहां नारनौल में लगा दे तो बड़ा सक्सैसफल तजरूबा होगा तो इन सब बातों की तरफ सरकार का तवज्जुह दे। यह हमारा इलाका जब पटियाला स्टेट में था तब भी निगलैक्ट किया जाता रहा फिर जब पैप्सू में था तबभी निगलैक्ट किया जाता रहा और बाद में पंजाब में आ गया था तब भी निगलैक्ट किया जाता रहा है। सो हमारे जिले की तरफ खास ध्यान दिया जाये। इतना कह कर मै खत्म करता हूं।

Chief S.P. Jaiswal (Karnal): Mr. Chairman, in the matter of General Administration large amounts are demanded but no efforts appear to have been made toward economy in the expenditure. There are Circuit Houses and Rest Houses. These are the symbols and legacy of a colonial rule. Nowhere in the world in any independent country we have these. These are really for the comfort of the officers in the Government. Large sums of money are spent udder these heads. A sum of Rs. 60,000 is sought for only furnishing one single Rest House at Simla. Some of these Rest Houses are specially air-conditioned for the use of the officers. In a State like ours where we need money for development this is a most unnecessary expenditure. Then there are yet the luxury cars for the use of Government officers and others and large sums are spent on these. Some of these cars are air-conditioned. These can easily be dispensed with and

replaced by much cheaper jeeps which will result in a lot of economy in the Government expenditure.

Then there are telephones at the residences of the Government Officers. These can also be dispensed with. These are luxuries and are only for personal comforts of the officers and serve no useful purpose of the Government.

There is a lot of expenditure on the free medical aid to the officers. One single officer has spent a sum of Rs. 25,000 for going to U.K. for the treatment of his eye. In a state like ours where people die everyday for want of medical aid, is it proper that free medical aid should be allowed to persons drawing salaries between Rs. 500 and Rs. 3,000. I would like to draw the attention of the Hon'be Finance Minister, through you Mr. Chairman, towards this expenditure and request that it should be eliminated.

Mr. Chairman, several members have spoken on the matter of Industry. Government has spend a large amount under this head. We have heard the Hon'able Member Shri Mittal who said that the industries in the Industrial Colonies are not functioning either efficiently or properly, I would like to say that the industries cannot be forced to function in particular colonies. If the industry has to function in the State facilities should be give to those who like to establish industries wherever they wish, The promises of facilities to be given to industries by the State Government are only a tall talk; they mean nothing. In fact, I am aware that industries are destroyed and licenses are cancelled and there is total apathy and indifference to the difficulties of industry. Under these circumstances no entrepreneurs are going to come to

establish industries in Haryana. If therefore, the Government is honest in its assurances it mush give all facilities to the industry and encourage the industrialists to establish wherever they wish.

Then there is the question of Roadways. The estimated profit of Rs. 82.38 lacs is only symbolic. No. income-tax is paid by the Roadways, no Sales-tax not even token tax, and if all these taxed is deducted out of the estimated profit if would become a figure of loss. All industries in the public sector are running at a loss and the same fate will be met by the public sector are running at a loss and the same fate will be met by the Milk Plant at Jind. I would therefore, request the Government to the cautious in this respect.

No attention appears to have been paid to the wastage in the Government expenditure which is the result of victimizations both administrative and political. I notice Government demands a sum of Rs. 4 lacs to meet decrial amounts. Government will have to spend more and more on dcrees against the Government will have to spend more and more on decress against the Government unless victimistation stops. There is case of which I am aware where police officers have been held guilty of criminal offences by the highest court of the State for illegal confinement, torture, falsifying police records and filling false affidavits. In this case the Government seeks to spend large sums of money to defends these people. This is a curious situation. If a citizen commits a criminal offence he is prosecuted by the Government but when a Police Officer commits a criminal offence and is help

guilty he is defended by the State and large sums of money in the form of appeals to supreme court are spent on him when in fact the Government is not a party and these are offences committed personally by the Police Officers.

Then there is political victimisation. The members of the Opposition have been asking for cars out of the Government quota but these are not being given and at the same time these are being repeatedly given to the members of the Congress Party. There is a case of the Sarpanch. The Hon'ble Chief Minister, who is not here at the moment, said that he has nothing to do with it. But how is it hen that there is a charge of *malafide* against him" In the end I would request the Hon'ble Chief Minister through you, Mr. Chairman, that he should desist both from administrative and Political victimisaton for I assure him through you, Mr. Chairman that if he does not do so we shall not let him get away with it.

श्री कंवर सिंह दहिया (रोहट, ऐस.सी.): चेयरमैन साहिब हमारा बजट घाटे में जा रहा है। उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए मगरजो मुझ से पहले भाई बोले है उन्होने सरकारी ऐस्टेबलिशमेंट की फसिलिटीज पर खर्च कम करने को कहा और उसे बारें में नुक्ताचनी की है। मै समझता हूं कि यह नाजायज है ओर जितनी भी फैसिलिटीज सरकारी कर्मचारियों को दी जाये उतनी ही कम क्योंकि जो भी ऐस्टेबलिशमेंट पर खच्र होता है वह रूल्ज के तहत होता है। इसलिज जो भी फैसिलिटीज उनकां मिी है वह ठीक है। और अधिक मिली चाहिए क्योंकि ऐडमिनिस्ट्रैशन में एफीशिएंसी लाने क लिए यह जरूरी है और अगर एफीशिएंसी रहेगी तो

सरकार मजबूत होगी औरसरकार मजबूत होगी तो प्रांत मजबूत होगा। लेकिन इतना में कहूंगा कि जिन सरकारी कर्मचारियों को सहूलियात दी गई है और फिर भी वह काम नही करते तो उनको सजा दी जानी चाहिए।

मै एक बात की तरफ सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के करैक्टररोल में जो एंट्री होती है वह बिल्कुल चुपचाप हो जाती है और कर्मचारी कंसर्नड को पता नही नही चलता। यह एक ज्यादती है क्योंकि अगर काई चीज झूठी भी लिख दी जाती है तो उन्हें उसके खिलाफ अपील करने के लिए मौका नही मिलता। इसलिए उसे एंट्री की हर बार इनफर्मेशन दी जानी चाहिए।

इसके बाद मै अपने हल्के की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कुछ वर्ष पहले रोहतक में बाढ़ आई थी उसकी रोकथाम के लिए एक ड्रेन नम्बर 8 निकाली गई थी।

श्री चेयरमैन: यह कां तक रैलेवेंट है इस वक्त?

श्री कंवर सिंह दहिया: जनाब रोहतक की बाढ़ की रोकथाम के लिए ड्रेन नम्बर 8 बनाई गई थी उससे बड़ी मौते हो रही है। यह एक अहम बात है जिसकी रेलैवैसी मेरे बोलने से बनती है। मुझे मौका अभी लिा है और मैं एक ऐसा मेम्बर उस इलाके से आया हूं जो पहली बार कांग्रेस की सीट से जीत कर आया है वरना पिछले 20 सालों में हमेशा अपोजीशन की कैडीडेट

ही जीतता अया है। इसलिए उस कांस्टीच्यूएंसी को कुछ आशाएं है ओरजो उनकी दिक्कतें है। उनकी तरफ वह लोग सदन का ध्यान मेरे द्वारा दिलवाना चाहत है। तो यह ड्रेन मेरे हल्के के बीच में हों कर गुजरती है। इसका बजट मेरे ख्याल में खत्म हो गया होगा। मगर इस ड्रेन पर 4–5 पुल बनने बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके एक ओर आधी जमीन है और दूसरी ओर आधी है। उनके पास पहुंचने तक 7–8 मील का चक्क काट कर जाना पड़ता है। जिससे एक तो उन का समय बरबाद होता है और जमीन बिना जुती पड़ी रहती है। जिससे काफी नुक्सान होता है। इसी तरह इसमें पानी भरे रहेने के कारण स्कूल के बच्चों को दूसरी पार स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आती है। कुछ बच्चे किसी वक्ति समय बचाने के लि सीधे पानी में ही कुद कर जाना चाहते है तो वे पानी के अन्दर बाज़ दफा बह जाते है और यदि आप देखे तेा उनकी मिनी ही लाशें उन ड्रैन में मिलेगी। अगर बजट प्रावेजीजन न भी रहा हेा, तो भी मै समझता हूं कि इन 4–5 पुलों का बनाना इतना जरूर है कि उसके लिए प्रोवीजन किया जाना चाहिए। यह पुल गोरडमाजरा और खरखोदा चौलका व थाना कलां के बीच इन जगहों पर बनाए जाने चाहिए। अगर इस बार भी कुछ न हुआ तो लोगों में कांग्रेस के प्रति फिर से निराशा फैलेगी और यह हो सकता है। कि कांग्रेस की आयंदा मदद न करें इसलिए इन पुलों की तरफ जरूर तवज्जुह दी जानी चाहिए। एक धान का जा मिडिल स्कूल है वह अपग्रेड होना चाहिए। खरखोदा को गलर्ज हाई स्कूल और डिस्पैंसरी की जरूरत है। मै तो बजट के बारें में

इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी रूपया रखा जाए उसकों सारे हलकों में बराबर बांट कर लगा देना चाहिए चाहे वह सड़कों मे लगे या किसी और काम में लगे परन्तु बराबर का पैसा सब हलकों में लगाना चाहिए और जैसे एक घर के सभी बच्चों को खाना एक सा मिलता है और यह नही होना चाहिए कि एक बच्चा बड़ा हो गयातो उसका खाना ही बन्द करदों और दूसरों को देते रहे या बड़ा ज्यादा खाता है तो सिर्फ उसी के लिए खाना हो और सब भूखे मरते रहे। यह नही होना चाहिए सब हलकों में बराबर का पैसा खर्च किया जाये। इन शब्दों में आपका धन्यवाद करता हूं और मै ज्यादा बोलने की जरूरत नही समझता।

श्री प्रताप सिंह दौलतपुर (बाडोपाल): यहां हमारे वित्त मंत्री महोदया ने कुछ सुझाव मांगे थे। मै समझता हूं कि यह जो रिपोर्ट हनुमन्तैया की है। इसमें वह सब सुझाव आ चुके है। यह पढ़ ले। इस में लिखा है:—

"One of the difficulty problems, Punjab is facing is water logging in country side. I May add that the crucial problem that is facing the administracton in Punjab in its various officer. is paper logging. Too may files, too much paper work, to manylevels and too many personnel are clogging the administraction at every stage."

मेरे ख्याल में यह काफी है। इसके बाद मे। कुछ दफतरों में जो फाइले चलती रहती है। और बहुत दिनों तक डिसीजन नही हो पाते उसकी तरफ वजीर साहिब का ध्यान

दिलानाचाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग में इम्प्रवमेंट किया जाए ओर फाइलें जल्दी मूव करे। एक एक पी.यू.सी. नौ नौ हाथों में गुजरता है और इनकी बड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। बहुत से दफतर बेकार है जैसे कि–(विघ्न) कंट्रोलर आफ स्टोर का आफिस है उसमें आई.ए.एस. और आइ.पी.एस. के अफसर सिर्फ ऐक्सपैरीमेंट करते रहे है जिसकी वजह से डिले हेाता रहा है। इस महकमें की जरूरत ही क्या है कमेटियों मुकर्रर को सकती है जिनमे हैड़ आफ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रटिव सैक्रेटरी का नुमायंदा और फाइनैन्स सैक्रेटरी का नुमायंदा हो। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी परचेज कमेटियां बन सकती है।

जब कोई वैलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट कोई स्कीम चालू करती है, तो वह जस्टीफिकेशन मांगती है। उस वक्त जस्टीफिकेशन तो बड़ी लम्बी–चौड़ी दी जाती है, मगर उसे बाद काम नही होता। बहुत से मुलाजम ऐसे रखे हुए है जिनकों कोई जरूरत नही होती, वह सारा साला बेकार बैठे रहते है और तरखाहे लेते रहेते है। यह खर्च बचाया जा सकता है। इसके इलावाएक एक महकमें मे अंडर सैक्रेटरी, दो दो डिप्टी सैक्रेटरी और उनका स्टाफ लगा हुआ है जो कि आसानी से कम हो सकता है। चेयरमैन साहब, मुझे मालूम नही कि आया लायबिलिटीज और ऐसैट्स का हिसाब किताब मौजूदा बेसिज पर किया गया था पिछला हिसाब भी मद्देनजर रखा गया कि नही। इस चीज का सारा हिसाब किताब किया जाए ज्वायंट पंजाब में कितने स्कूल, कालेज

और हस्पताल बने थे और हमारे हिस्से कितने आए है और उस का हिसाब लगा कर हिन्दी गवर्नमेंट से कहा जाए कि हमारे हा इतने स्कूल, इतनीसड़के और इतने हस्पताल बनने चाहिए थे जिनके लिए हमं इतना रूपया मिलना चाहिए ताकि हमारा जो अंडरडिवेल्पड एरिया है। हमें इसको डिवैल्प कर सके।। यह तो कोशिश होती रहे कि हमें पैसा मिले और स्टेट का यह फर्ज है कि लोगों को सारी सहूलतें मुहैया हो, हर आदमी यह चाहता है कि मेरे हल्के में पहले हो लेकिन जब तक स्कीमों की इम्पलीमेंटेशन नही होती उतनी देर तक कोई तरक्की नही हो सकती। एग्रीकल्चर के सम्बन्ध मं मै निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके मे भी हाइब्रिड बीज दिए जाएं ओर लोगों को इनसैक्टीसाइड्ज भी दिए जाएं ताकि वह पैदावार ज्यादा कर सकें। चेयरमैन साहब, हम देखते है कि सब चीजों के भाव आए दिन बढ़ा दिए जाते है लेकिन जमींदार जब अपनी फसल मार्किट में लाता है तो सह एक दो तीन कह कर नीलाम कर दी जाती है। बाद में जब उसकी दूसरी चीजें खरीदने जाना पड़ता है तो वह महंगी मिलती है। किसान को उसकी फसल की कीमत जायज मिलनी चाहिए और उसे खुली छुट्टी होनी चाहिए कि वह जहां चाहे अपनी प्रोड्यूस को ले जाए। लेकिन होता यह है कि उस के ऊपर पाबन्छी लगा दी जाती है कि तुम जिल से बाहर अपनी फसल दूसरे जिलों में भी ले जाकर नही बेच सकते। तो मै यह समझता हूं कि उसके साथ बेइन्साफी है। जब बाकी चीजो ंपरकोई पाबन्दी नही तो फिर उसकों भी क्यों चैक किया जाता है? जमींदार को अगर जायज

कीमत मिलेगी तो दूसरे व्यापरको भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उसने बाकी सारी चीजें बाजार से खरीदनी होती है। दूसरी तरफ यह दलील दी जा सकती है कि जो कंज्यूमर है उनका भी ख्याल रखना होता हैं मै निवेदन करूंगा कि हरियाणा में 70 फीयदी किसान है ओर 30 फीसदी लोग ऐसे है जो कि अनाज मोल लेते है गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों का रिम्युनरेटिव प्राइस देकर कंज्यमर्ज को सस्ते भाव पर दे और बाकी की कीमत सबसीडाइज करें। अमरीका में आप जानते है कि जब ज्यादा पैदावार हो जती है तो गवर्नमेंट अनज को खरीदका समुद्र में गेर देती है, लेकिन यहां पर तो किसान को नुक्सान पहुंचाने वाली पालिसी अख्तियार की जाती है जो कि देश के लिए हानिकारक है। जमींदारों को सहूलते देने से मुल्क का ताक बढ़ेगी। कपास के मामले में पिछले साल बड़ी धांधली मची। 240 रूपये से 140 रूपये हो गई मगर धोती के जोड़े का भाव 30 रूपये से 35 रूपये हो गया धोती जोड़ा कपास से ही बनता होगा फिर यह कैसा इन्साफ है?

श्री चेयरमैनः अब आप बैठ जाइए। (आनरेबल मेम्बर बैठ गए)

श्री गणपत राय (दादरी, एस.सी.): चेयरमैन साहिब, आज सामान्य प्रशासन, कृषि और सहकारी उद्योग पर बहस चल रही है। इसमे संन्देह नही कि सामान्य प्रशासन में भ्रष्टाचारी है। मै मानता हूं इ बात के और साथ ही साथ यह भी मानता हूं कि यह इस सरकार का ही दोष नही है बल्कि हमारी जो लोकतन्त्र प्रणाली है

वह ऐसी है कि इससे सारे राष्ट्र मे यह बीमारी फैली हुई है। हमने आज इस विषय के बारे में, जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, नये सिरे सज सोचना है क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम इस और बैठे हो या उस ओर बैठे हो, पालिटीशन हों यह सरकारी कर्मचारी हो। क्योंकि चेयरमैन साहिब, ताली एक हाथ से नही बज सकती। हम इस हमाम के अन्दर सभी नंगे है। अकेले सरकार को ही दोष दना कि यह भ्रष्टाचारी है, मै यह मुनासिब नही समझता। हम जनता से वोट लेकर आते है, सभी भाई अपने हृदय पर हाथ रख कर देंखे, जिनसे हमवोट लेकर आते है वह आप से कुछ न कुछ आशा रखते है। वह जब वोटें दैते है तो सोचते है कि यह सदस्य असेम्बली मे जाकर हमारी कुछ मदद करेंगे लेकिन चेयरमैन साबिा, मुझ दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मुलाजमों से रिश्वतखोरी को निकाने का सवाल आत है, किसी मुलाजत को सजा देने का सवाल पैदा होता है, तो हम मेंसे ही जनता के नुमायंदे उस मुलाजम को बचाने की कोशिश करते है। इस तरह भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सता है? विरोधी भाई जो दोष देते है कि सरकार और सरकारी मुलाजम भ्रष्टाचारी है उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये। मै इस बात को मानता हूं कि इसका उपाय हो सकता है अगर हम ठण्डे दिल से सोचे। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हम इकट्ठे बैक कर कोई न कोई तरीका निकल सकते है जिस से कि यहबीमारी प्रदेश से दूर की जा सके। चेयरमैन साहिब, जितने पालिटीशन है, आम देखने में आता है कि वे हर रोज छोटी छोटी बातों में दखल देते है और

कर्मचारियों से उलटे–सीधे काम करवाने के लिएये उन पर दबाव डालते है। यदि वह ऐसा करना छोड़ दे तो सरकारी मशीनरी में कम से कम इन्टरफीयरेंस करें, ज्यादा पेचीदगियां पैदा करने की कोशिश न करें तो आपने आप की सरकार मशीनरी अच्छे ढंग से काम करेगी ओर सरकार का प्रशासन स्थिरता से चलेगा। मुण्े दुख होता है और मै मानता हूं कि हमारे दफ्तरों में रिश्वतखोरी बहुत बढ़ री है, जैसा कि श्री रूप लाल महता जी ने तफसील में बताया, जिस से जनता को बहुत कष्ट होताहै। भ्रष्टाचार बहुत घटिया दर्ज तक पहुंच चुका है, बिजली का महकमा ले लो, नहर का महकमा ले लो, निर्माण का महकमा ले लोा, बी.डी.ओ. के दफ्तर यहसभी इस बीमारी का श्किारहै। अगर हम कठोरता से काम करें और ईमानदारी से सोच करक चलें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। चेयरमैन साहिब, मेरे से पहले बहुत सारे मेम्बर बोले है और उन्होने अपने अपने इलाकों के बारैं मै, जाहां से वह आए है, बहुत कुद कहा है। कई भाईयों ने कहा कि उनके इलाके के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है लेकिन मै कहना चाहता हूं कि जिस इलाका से मै आया हूं जिला महेन्द्रगढ़ से उसके साथ तो सौतेली मां जैसा व्यवहार भी नही हो रहा है। उसे साथ ता बगैर मां बच्चे जैसा और एक यतीम बच्चे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जो कुछ मित्तल साहिब ने वहां के बारें में ब्यान किया है वह दुरूस्त है। यह जिला कृषि के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है। संयुक्त पांजाब में हरियणा वाले कहते थे कि सारा हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है और जितनी सुविधाये है वह पंजाब वाली ही ले

जाते है। अब जब हमारा अलग हरियाणा बन गा है ते मै समझता हूं कि इस हरियाणा में भी हम टेल पर है और हमारे साथ वही व्यवहार होता है जो संयुक्त पंजाब में सारे हरियाणा के साथ होता था। तो मै कह रहा थाकि कृषि के मैदान में मेरा जिला बहुत पीछे है। वहां पर नहर तो नही पहुंची लेकिन नहर की पूंछ जरूर पहुंची है और वह भी ऐसे सूरत में कि माइनर जो वहा पर बना उसमे रेतीला इलाका होने की वजह से ज्यादा पानी नही चल सकता। जब हम शोर डालते है तो कुछ पानी छोड़ा जाता है लेकिन उस पानी के छोड़ने से किनारे कट जाते है और किसान को उस पानी का पूरा फायदा नही पहुंच सकता। उसके लिए मै सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर कृषि को बढ़ावा देना चाहते है तो वहां जो माइनरहै उसे पक्का किया जाए। वहां पर बिजली की भी बड़ी कमी है। मै मंत्री महोदय को अपने साथ उस इलाका में ले गयाथा और उन्होने लोगों की तकीफ को देखा है। मै आशा करता हूं कि वह वहां पर बिजली के जाल बिछा देंगे ताकि वहां पर ट्यूबवैल लगाए जा सके। मेजर साबिह और मित्तत साहिब ने जिक्र किया था वहां पर कुए लगाने के लिए बोरिग मशीन की जरूरत है। मै भी उनकी ताईद करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वहां बोरिग मशीन का इन्तजाम किया जाए ताकि लोग ट्यूबवैल लगा सकें। एक और बहाना बनाया जाात है कि वहां नहर नही पहुंच सकती क्योंकि वह इलाका इतनी ऊचाई पर है कि वहा पानी नही चढ़ सकता है। अगर ऐसा है तो मै कहूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए और

ट्यूबवैल लगाए जाएं। मै एक ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखता हूं जिसे हरिजन कहा जाता है। जहां तक इन लोगों का इस पिछड़े हुए वर्ग के साथ ताल्लुक है मै उसका भी जिक्र करनाचाहता हूं। यहा दावा किया जाता है और कहा जाता रहा है कि सरकार हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और उन्हें ऊंचा उठाने के लिये बड़े उपाय कर रही है और धन जुटा रही। इस बारें में मै यह कहना चाहता हूं कि आजकल हरिजनों के साथ बहुत बुरी गुजर रही है। चुनाव हो चुके है लेकिन उसके बाद अब सारा नजला गरीब हरिजनों परगिर है। समाज विरोधी तत्व उनके पीछे हाथ धो कर पड़े हुए है और उन्हें हर तरीके से तंग कर रहे है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी कहा था कि हरिजनों को कई हल्कों में वोट नही डालने दिए गए और समाज विरोधी तत्वो ंने उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया है। मै कहना चाहता हूं कि विधान ने जो उन्हें हक्क दियाहै उसे भी उन्होने उन्हें इस्तेमाल नही करने दिया। अब कांग्रेस सरकार बनी है तो उनके दिलों मे थाकि अब उनक दुखों का अन्त होगा लेकिन में मुख्य मंत्री जी का यान इस बात की तरफ दिलानाचाहता हूं कि आज हरियाणा में हरिजनों के साथ बहुत जुल्म हो रहे है जिनको देखकर हमें शर्म आती है। मै उनके गांवों के नाम ले सकता हूं जहां आज हरिजनों का सोशल बाइकाट हो रहा है, नाकाबन्दी हो रही है और उनकों घरो ंसे बाहर नही निकलने दिया जाता। हरिजन वैलफयेर मिनिस्टर साहिब बैठे है, मैने उन्हे बताया था और उनको ंदेा गांवों पारलावास और रामलावास के नाम भी बताए थे जहां पर कि यह हालात हो रहे हैं

वहां पर हरिजनों को घरों से बाहर निकलने नही दिया जाता। हमने उनकी मारफत इस बारें में ऐस.पी. साहिब को दरखास्त भी दी थी लेकिन अभी तक पता नही लगा कि उसका क्या बना है। अभीतक उस बारें में कोई ऐक्शन नही लिया गया है। यही हालात हांसी में हो रहे है और जींद में हो रहे है। एक उजियाना गांव है जाह पर हरिजनों को बुरी हालत है और भी इसी तरह से कई गांव है जहां पर हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और हरिजनों को इस समाज विरोधी तत्वों से बचाना चाहिए। फिर हरिजनों को जमीनें देने की बात बहुत चलती है। मै तो समझता हूं कि जमीन का मसला तो हरिजनों के लिए एक मृगमारीचिका बन गया हुआ है। नजूल, सरप्लस ओर पंचायती जमीनों के बारें मे जो कानून है उन के ऊपर कोई अमल नही हो रहा है। सवानी का एरिया ही ऐसा है जहां पहर हरिजन को इवैक्युई प्राटी मिल सकती है लेकिन इसलिए कि हरिजनों को जमीन न मिल जाए वहां के लिए स्पैशल कानून बना दिया गया हुआ है।

श्री चेयरमैन: आप अब एक मिनट में खत्म करें।

श्री गणपत राय: मै सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरिजनों की देखभाल के लिए एक ही हरिजन वैलफयेर का महकमा था लेकिन उसे खत्म कर दिया गया है, ऐसा नही होना चाहिएये। फिर बड़े दुख की बात है कि हरिजनों के लिए एक इवैलूएशन कमेटी बनी थी और उस ने एक

रिपोर्ट भी दी थी लेकिन उस पर कोई अमल नही किया गया। मै सरकार से अपील करता हूं कि उस रिर्पोट पर अमल किया जाए और उस रिपोर्ट की कापी हरेक मैम्बर का दी जाए ताकि उन्हें पता लगे कि उसमे कया रिकमैडेशनज है। इसके अलावा मैं अर्ज करता हूं कि हरिजनों के साथ सविसिज में ओर उसमें प्रोमोशन्ज में बड़ी बेइन्साफी हो रही है और उन्हें उनका हक्क नही मिल रहा है। मै सरकार से दरखास्त करता हूं कि अगर वह हरिजनों के साथ इन्साफ चाहते है और उनका भला चाहते है ते वह एक स्पैशल सैल कायम करें और एक स्पैशल आफीसर आन डियूटी मुकर्रर करें जो हरिजनों की तकलीफ को देखें, सुने ओर दूर करने का यत्न करे। अब अंत में मै सरकार से अपील करता हूं कि वह हरिजनों की तकलीफो को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए ताकि उनका इस सरकार से विश्वास बन सके और वह सुख का जीवन बिता सकें।

चौधरी अब्दुल रजाक खां (फिरोजपुर–झिरका): चेयरमैन साहिब, आज जो मद हमारे एवान की बेहतरी के लिये सदन में ज़ेरेबहस है, इसके बारमें अवाम को से 20–22 साल पहले से यह उम्मीद थी कि आजादी मिलने के बाद हमें इन्साफ मिलेगा। लेकिन इन्साफ नही इससे उल्ट हुआ। जितनी भी पालिसीज है उसे अवाम बेचैन है। हाउस में जितने भी मैम्बरान बैठे है उन सबा के असूल अलग अलग है। अवाम की अपने नुमायंदों पर नजरें लगी हुई है। और देख रहे है कि ये नुमांयदें हमारे लिये क्या

पालिसीज बनाते है, क्या क्या इन्तजाम करते है। अफसरानको जनता की बेहतरी के लिएये क्या क्या काम काम मिलता है ओर वे कहां तक उस पर अमल करने के लिये पाबन्द है? इस हाउस में बोलने वाले बहुत स भाइयों ने कई किस्म की शिकायते की है और उन्हें शिकायत करने का कोई हक्क नही है क्योंकि जो पालिसीज अख्तियार की जाती है। वह उन्ही की पालिसीज है, वे बीस सा से इन्ही पालिसीज पर चले आ रहे है। इलैक्शनों के दिनों में उन्ही की पालिसी चलती रही। मेरी इस संबंध में खासतौर पर यह अर्ज है कि जो भाई इस हाउस में बैठे है वे इस बात का सोचे कि खराबी किस जगह पर है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपने हाथ मे लेने लगे हे। जितनी भी गलत पर है। आज हम एडमिनिस्ट्रटिव मशीनरी को अपने हाथ में लेने लगे है।। जितनी भी गलत चीजें है वह एडमिनिस्ट्रेशन में नाजायज दखल देने से ही पैदा हाती है। अवाम की बेहतरी को एक तरफ छोड़ कर हम अपनी इलैक्शन स्टंट बनाने और फाइनैशियल प्राग्रैस करने में लगे हुए है। जब तक हरियाणा में इस लानत को खत्म नही किया जाता तब तक हरियाणा के अवाम बचैन रहेंगे।

जब तक रूलिंग पार्टी का ताल्लुक है इन्होने 15 तारीख को सदन में ओथ ली ताकि वे अपने मुल्के के लिये, अवाम की वफादारी के लिये ज्यादा से ज्यादा फर्ज अदा कर सकें। लेकिन मै समझता हूं कि ये सब फरायज भूल गये है। उनहें सिर्फ हकूमत

का नही नशा है, जिसके लिए जनता ने भेजे है उसका कोई ख्याल ही नही है। मै उन्हें बता देना चाहिता हूं कि वह जो कुछ करते है उन्हें अवाम को उसका हिसाबा देना पड़ेगा। उनको पता नही कौनसी मखलूक में जन्म लेना पड़ेगा। वे समझे है कि अफसरान हमारे इशारे पर चलेगे, हमारा इन पर पूरा पूरा हक है, जो काम करवाना चाहें करवा सकते है और हमारे इशारे पर नही चलेंगे तो तबदील करवा देंगे। उन मेम्बर साहिबान को यह पता नही कि एक अफसर के तबदील होने से कितना नुक्सान होता है। एक अफसर जो अपने इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, उसकों खजाने से टी.ए. और डी.ए देना पड़ता है। जो स्कीमें उस अफसर ने शुरू की होती है उन स्कीमों को बहुत नुक्सान पहुंचता है। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में नाजायज दखल नही देना चाहिये, इससे मुल्क को बहुत नुक्सान हेाता है। मै तमाम मैम्बरान से अर्ज करता हूं कि वे अपने मुकाम पर अपनी पालीसीज को देखे कि किस तरफ से काम हो रहा है। अगर किसी जगह करप्शन हो रही है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। मैने ऐसा भी देखा है कि जो भाई कांग्रेस के हिमायती थे या जो इलैक्शन में हार गये है वे अफसरान के पास जाकर बैठते है और जाहिर करते है कि हमारी पाटी की हकूमत है, इसलिये हमारे इशारे पर चलो। आपको हमारे इशारे पर चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नही करेंगे तो नुक्सान उठाना पड़ेगा। अगर कोई अफसर ईमानदार हो और कोई गलत काम करने के कलये तैयार न हो तेा उसकों बदल दिया जाता है। उन भाईयों को ऐसा नही

करना चाहिये, जो वक्त ये अफसरान को करप्ट करने में लगाते हे। वह वक्त मुल्क की भलाई के लिये लगाना चाहिये, इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमेंट के लिये लगाना चाहिये और अपनी जाती तरक्की के लिये नही लगाना चाहिये।

जहां तक सजैशन देने की ताल्लुक है। वह अमल करने से ताल्लुक रखती है। मै समझता हूं कि ट्रैजरी बैचिज और अपोजीशन बैचिज पर जो भाई बैठे हुए है वे सब देखें कि उनके क्या फरायत है। अगर वे अपने अपने मुकाम पर अफसरान को चैक करते रहे ता उनके सब गिले शिकवें दूर हो जायेंगे। अफसरान से कोई गलत काम न होने दे। लेकिन मैम्बर साहिबान, लालच में आकर अपने फरायज को भूल जाते है। यह लालय तो बड़ी देर से चल रहा है। कि अफसरान पर हमारा हक्क है, इन पर हमारी ही पालीसी चलेगी, जो कुद हम चाहते है उन्हें वही करना पड़ेगा। मैम्बरान को यह लालय छोड़ देना चाहिये वरना कुदरत देख रही है, ह उनके गुनाहो ंका जरूर बदला लेगी। (व्यवधान)। आजादी से पहले, हम मुल्क में एक नई किरण निकलने की उम्मीद रखते थे लेकिन आजादी मिलने के बाद जो थोड़ी–बहुत रोशनी दिखाई देती थी वह भी चली गई। मुल्क में सारे काम उल्टै ही हो रहे है। जिन लोगों को देश की भलाई के लिये काम रकने थे वे सारे के सारे हकूमत के नशे में डूबे हुए है और वे महसूस करते है कि हम पांच साल क`लिये आ गये है। लेकन उन्हें यह पता ही नही है कि पिछली दफा भी चन्द दिनों के अन्दर असैम्बली तोड़ दी गई

थी। इसलिये हमारे भाइयों को हकूमत के नशे को छोड़ कर अवाम की बेहतरी के लिये जुट जाना चाहिये और उनके कारनामे ऐसे होने चाहिये जैसे कि एक आजाद मुल्क के निवासियों के हेाते है। हमारी तरक्की का दारोमदार हमारी अकल पर मुनहसर है। हमारे बजुर्ग यह कह गये है। कि सबको अच्छी बातें बतायें, बुरे रास्ते पर किसी को आमादा न करें। जब तक हमारी पालीसी, हमारी दिमाग, भलाई वाले कामों में नही चलेंगे तब तक कोई काम नही होगा।

Mr. Chairman: Khan Sahib, time is over

चौधरी अब्दुल रजाक खां: थोड़ा सा टाइम और दे। मै अर्ज कर रहा था कि हमने अपनी जीवन में दूसरों को आराम देना है। अगर अच्छे कामों को छोड़ कर बुरे कामों की तरफ हमारा जीवन इस्तेमाल होने लगा तो मै समझता हूं कि शायद ही किसी को मौत के बाद इन्सान का जीवन मिले। इसलिए मै मैम्बर साहिबान से अर्ज करना चाहिता हूं कि अवाम के लिये अच्दे काम करें और अपने आप को सुधारें। सदन मैं कुछ भाई तमाशबीन है, उनकी नजरें हम पर लगी हुई है। कि हम क्या बोलते है? इन्हें बातें सुनने अमल है। लेकिन मै इन्हें कहना चाहता हूं कि एक इन्सान दूसरे इन्सान के लिये काम करें तेा बातें न सुने।

श्री चेयरमैन: चौधरी साहिब, आप किस डिमांड पर बोल रहे है?

चौधरी अब्दुल रजाक खां: अब मै जनरल डिमांड पर अर्ज करूंगा। पुलिस दफा 107 और 151 के तहत जो कार्यवाही करती वह चालान करने कतक ही महदूद नही है। लोगों के ऊपर बड़े जुल्म होते है। चेयरमैन साहिब, जो आदमी जालिम होता है वह ताकतवर होता है। वह अपने मेम्बर को ऐप्रोच कर लेता है, रिश्वत देकर और रिश्ता निकाल कर अपना बचाव कर लेता है। तो मै यह अर्ज करूंगा कि इस रिफ सरकार गौर फरमाए ताकि गरीब लोगों को जुल्म न सहना पड़े बल्कि उन्हे न्याया मिल सकें। (विघ्न) चेयरमैन साहिबा, हाल ही में मेरे हल्के में एक घटना घटी है। मौजा सुड़ाका और मछरौली की दो पार्टी ने बारात को घेर लिया। जब मजलूम पाटी थाना नूह में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस ने सीनाजोर पार्टी से मिलकर बजाय मजलूम की इमदाद करने के या उन के हिफाजत देने के उनको धमकाया और उनकी रिपोर्ट दर्ज नही की। उनकी साईकल भी थाने में रख ली। लोगों के कहने सुनने के बाद उन्होने बारात को तो जाने दिया मगर लड़के के बाप को वही पर रख लिया। लोग मेरे पास आए और मै वहां गया मैने उसे बातचीत की और कहा कि भाई यदि तुमने इससे बदला ही लेना है तो कम से कम इस वक्त तो न लो, और कई मौके आएंगे, ले लेना। इस वक्त तुम इसे जाने दो। मेरे इतना कहने के बाद उन्होने बेचारे उस आदमी को छोड़ा और वह बारात में जाकर शामिल हुआ। साईकल भी मैने उनको दिलवाई। चेयरमैन साहिब, इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है

कि वह अफसरों को कुछ ताकत दें ताकि ऐसी घटनाएं न घटे और लोगों को बढ़िया इन्तजाम और न्याया मिल सकें।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : सभापति महोदय, हमारे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश भी है और एक प्रदेश हमारा है पंजाब के बंटवारे के बाद एक छोटा सा प्रदेश बन गया है। छोटे प्रदेश बनने के कुछ फायदे भी होते है मगर हमारे यहां के फायदे कुछ दिखाई नही देते। एक छोटा प्रदेश होने के नाते हमारे लोगों के ऊपर प्रशासन का बोझ कम होना चाहिये और जितनी कड़िया है उनको कम किया जाना चाहिये। छोटे प्रदेश के अन्दर जो बड़े प्रदेश की प्रणालियों होती है, प्रथाएं होती है वे कोई बहुत ठीक नही रहा करती। हमारे प्रदेश के अन्दर जिला स्तर के प्रशासन में और प्रदेश स्तर के प्रशासन के बीच किसी भी महकमें की भी कोई कड़ी दूसरी नही होनी चाहिये। बड़े प्रदेश में तो वे ठीक हो सकती लेकिन छोटे प्रदेश में यह बोझ का कारण बनती है। आप जानते है कि हमारे यहां मैसूर से एक साथी हनुमन्तया जी आए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म आयोग बनाया गया था। उस उायोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सिफारिश की थी कि प्रशासन में खर्चे को कम किया जाए। मिसाल के तौर पर प्रशासन का बोझ कितना बढ़ा है मै एक मिसाल देता हूं जब इकट्ठा पंजाब था तो यहां चंडीगढ़ के अन्दर एक खजाना का अफसर होता था। उस खजाने अफसर की मांग थी कि मेरे पास काम ज्यादा है इसलिए एक मददगार चाहिये लेकिन उसकों उस

वक्त एक मददगार असिस्टेंट नही दिया गया। आज चंडीगढ़ के अन्दीर तीन खजाना अफसर है ओर तीन मदद अफसर है। हरियाणा के भी दो अफसर है। एक छोटी सी मिसाल मैने आप को दी। मै मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्छर अब चूंकि राजनीतिक हालांत कुछ अच्छे होते दिखाई देते है इसलिए इनका फायदा प्रदेश को पहुंचना चाहिये। प्रदेश को फायदा पहुंचाने के लिये सबसे जरूरी यह है कि हम सोचे कि हम प्रशासन का बोझ किस ढंगसे कम कर सकतेहै। सभापति महोदय, एक समय था जब सरकारी नौकरी करने वालों की पैंशन पर जाने की आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वष्र रखी गई थी। हमारे देश के विधान के मुताबिक हम आसानी से किसी सरकारी कर्मचारी को बाजार या गली में फेंक नही सकते। सरकारी कर्मचारियों के अपने हकूक है, उनकी रक्षा के लिये अदालते है, कायदे है और कानून है। लेकिन उन सबको मानते हुए सब बातों की मान्यता रखते हुए कुछ न कुछ बोझ कम किया जा सकता हैं उसके कम करने की कोशिश करनी चाहिये। जब पंजाब बंटा तो राजनीतिज्ञों से कोई सलाह नही ली गई। सरकार नौकरियों का भी बंटवारा किया गया। यह नही देखा गया कि है छोटा या हरियाण प्रदेश कर्मचारियों के इतने बड़े खर्च को बर्दाश्त कर सकता है कि नही। मै तो मानता हूं कि पिछले डेढ़ साल का ऐसा वक्त रहा जिसमें हम शांति से सोच नही सकें कि कितना हो हम वापिस कर सकते है, कितना बोझ किस महकमें में घटना चाहिये लकिन अब इसकी तरफ बड़ी शांति से हम को विचार करना होगा और देखभाल

करनी होगी। सभापति महोदय, इसी सिलसिलें में बजट के अन्दर जो आंकड़े छपे है, उनकी ओर मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बावजूद इस बात के कि हरियाणा के अन्दर प्रशासन का काफी बोझ है, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सरकार की हिस्सेदारी, चाहे वह हिस्से की शक्ल में या डिवैन्चर खरीदने की शक्ल मे ंया जितने भी और अदारे है उनकों कुल तादार 68 है औ इन 68 मे ंसे भी आप को जानकार ताज्जुब होगा कि 43 अदारे ऐसे है जिनके हिसाब का बंटवारा आज तक पंजाब और हरियाणे में हम नही करा सकं। पंजाब स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कानून के तहत आपस में बंटवारा करने ओर मतभेद दूर करने की मयाद दो साल रखी गई है। बाकी 25 अदारों में से 7–8 के करीब अदारे तो ऐसे है जो हरियाणा प्रदेश बनने के बाद नए कायम किए गए है। बाकी जो 17–18 अदारे रहते है वे ऐसे है जिन मे ंपंजाब के या हिमाचल प्रदेश के हिस्से शामिल नही हैं उनका उनमे ंकोई दखल नही है मुझको तो चेयरमेन साहिब, बजट में कोई बात दिखाई नही दी सिवाह सैन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक जींद के बारें में जिक्र किया गया हैं कि संगरूर को–आप्रेटिव बैक से जीद का हिस्सा संगरूर सैट्रल को–आप्रटिव बैंक से मिल गयाहै। पौने दो सालामें यह प्रशासन क्या करता रहा यह मेरी समझ मे ंनही आतौ। जब कोई प्रशासन बंटवारे के बाद अपना हिस्सा लेने के लये कोई कार्यवाही ही नही कर सकें तो, चेयरमेन साहिब, मै नह ीसमझ सकता कि प्रदेश की तरक्की कैसे हो सकती है।

सभापति महोदय, ये जितने अदारे है उनका बहुत सारों का खेती से या सहकारिता के महकमें के साथ या उद्योग धन्धो ंसे ताल्लुक है। इन सब अदारोंका इन महकमों से ताल्लुक है इनकी बुनियादी फैसला भी नही कर सकें या न करा सकें हो ता उनसे हम कितनी आशा तरक्की कराने की रख सकते है।

अब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, जो खेती की पैदावार करते है। उनके दिल को जीतने की ज्यादा आवश्यकता है जहां पानी ओर दूसरी खेती की चीजें और अच्छे बीज और अच्छी मशीनों की आवश्यकता है वहां हरेक किसान के मन को जीतने की कभी आवश्कता है।

सभापति महोदय, एक जमाना था जिस वक्त हिन्दुस्तान के अन्दर एकोनोमिस्ट इस बात की बहस किया करते थे कि लैंड रैवेन्यू रैंट है या टैक्स है क्योंकि उस वक ततो विदेशी सरकार थी कोई इसको रैंट मान कर चला सकता था लेकिन आज तो जनता की सरकार है कया हम यह कह सकते है। कि यह जमीन पर रैंट है। बज जमीन पर रैंट हो और दूसरी चीजों पर रैट सरकार ने ले तो एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, भेद–भाव है। तो इस भेद भाव को रखेगे तो किस तरह से किसानों मे जोश पैदा होगा।

प्रापटी टैक्स जो है वह तो एक मकान पर लगता ही नही अगर उसे अन्दर उसका मालिक खुद रहता हो तो प्रापर्टी टैक्स तो माफ हो जाता है लेकिन जिसके पास पांच खुड है तो

लैंड रैवेन्यू उसको कोई माफ नही करता और प्रापर्टी टैक्स तो 3600 रूपये तक माफ होता है।

सभापति महोदय, यह प्रशासन की तरफ से सात–आठ साल लगे थे जब एक सैटलमेंट करने की कोशिश की थी। जब मरला टैक्स की कहानी सुनेगे आप तो, मरला टैक्स पर काफी खर्च किया गया और खर्च के बाद जो फैसला करना पड़ा कि उसकों छोड़ दिया जाय इसमें घाटा ही घाटा है। तो सैटलमैंट की शायद आवश्यकता होगी लेकिन दूसरे रूप से सोचने के लिये, दूसे विचारों को ध्यान में रख कर तो सैटलमेंट की कोई आवश्कता हो सकती है लेकिन आज पुरानी प्रथाओं की जा चालीस–पचास साल पहले की है देश के अन्दर उनका जिक्र कोई नीति निर्धारण मे करता है। तो वह काई सही तरीका नही होगा। एक जमाना था जिसे मं केन्द्रीय सरकारों में आमदन थ्भ उसमे भूमिकर का जो हिस्सा होता था वह 75 फीयदीतक पहुंचता था लकिन आज तो भूमि कर प्रदेशों की आमदनी कही पांच फीसदी, कही सात फीसदी बन गया है ओ हमारे ज्वायंट पंजाब में असेम्बली मे ंएक प्रस्ताव पास हुआ और मै मानता हूं पिछली सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास किया है कि पांच एकड़ तक भूमि क हमें मलिया माफ करना है ंतो इन हालतों को देखते हुए अगर हमें कोई सैटलमैट की जरूरत हे तो ठीक है वरना सैटलमैट ता एक तरह से कन्सालीडेशन से हो ही गई। यहां जिस तरह सैटलमैंट की बातें की जाती है ओर प्रशासन का जितना खर्च करना हाता है उसके बारमें एक महकमें

का मुझ तजुर्बा हुआ था। जब प्रदेश के अन्दर कन्सालीडेशन हुई तो कन्सोलिडेशन से पहल कई मोघो पर ही रह गया। जिस वक्त मुझे पंजाब में बिजली और सिचाई विभाग के मंत्री पर संभालने का मौका मिला था उस वक्त मैने जानकारी की थी कितने मोघे है जिनकी हम ने चकबन्दी कर दी थी कन्सालिउेशन के बाद, आपको जय जानकर ताज्जुब हहोगा कि 24 हजार मेंसे केवल साढ़े चार हजार की चकबन्दी हो सकी थी। छः सात महनी मुझे इस महकमें मे ंरहने का मौका मिला और 6 महीने में 15,000 मोघे की चकबन्दी की गई। दूसरी बात मै बापको बताऊ कि कन्सालीडेशन का काम खत्म होने के बाद उन अफसरों को काम देने का तरीका तलाश कर रहे है और आखिर में कोई भी और तरीका अब तक नही तलाश कर सके है।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि हमारी सरकार किसानों को पूरी सहूलियत नही दे रही है अगर सरकार पूरी सहूलियतें दे तो पैदावार बढ़ सकत है। यह आप सबको मालूम है कि भावों के कम होने मे हमारी सरकार बहुत बड़ा हिस्स तो गवर्नर राज का उससे में मानती है। एक जमाना था जब पंजाब प्रदेश से हरियाणे की मंडियोंा में आकर पंजाब का अनाज बिकता था लेकिन इस साल हरियाणे का अनाज पंजाब की मीड़ियों में जाकर बिका। सरकार ने 75 रूपये क्विटल गेहूं का भाव मुकर्रर किया और यहां पर 65 ओर 67 रूपये के हिसाब से बिका। तो आप अन्दाजा लागाये कि हरियाणे के किसानों को

कितने करोड़ों का घाटा हुआ जहां केन्द्रीय प्रशासन ने किसानों के गेहूं के भाव मुकर्रर करके एक तरफ उनके दिल को जीतने के लिये कदम उठाया था हमारे प्रदेश में गेहूं का भाव पूरा नही दिला सकी और किसानों को परेशान किया है। गांधी जी ने कहा है कि वह राज अच्छा अच्छा होता है जे कम से कम राज करता है और भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करता हैं यह बड़े दुख की बात है हमारे प्रदेश मं और पडोसी पंजाब प्रदेष के भाव में आठ साअैर सात रूपये का फी क्विटल फर्क रहा। तो इससे किसानों को प्रोत्साहन नही मिलता, उससे तो उसे दिल को ठेस पहुंगेगी हमें किसान की सहायता देनी होगी बस मै आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

प्रिसिपल ईश्वर सिंह (पूंडरी): चेयरमैन साहिब, आज चार डिमांड्ज हाउस के सामने है। मै उन्ही तक अपने आप को सीमित रखूंगा। पहली डिमांड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक किसी सिस्टम पर नही बल्कि परसनैलिटीज पर होता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। मिनिस्टर्ज को अपने महकमे के काम में कितनी लगन और तड़प हैै। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक यह बात आम है। कि इसमें करप्शन है। करप्शन का संबंध लोगों के स्टैडर्ड आफ लिविंग से भी है। अगर लोगों का स्टैडर्ड आफ लिविंग अपने जराये से ज्यादा है ता नैचुरली उनको अपनी जरूरियात को पूरा करने के लए दूसरे तरीके से पैसा कमाना

पड़ता है और करप्शन का आसा लेना पड़ता है। इन सिलसिले में मेरा एक सुझाव है कि स्टेट के अन्दर सरप्राइज रेडज होने चाहिये। ऐसा करने से इन मामले में काफी फर्क पड़ सकता है। जैसे पहले जमाने में राजा लोग भेस बदल कर फिरते थे, उसी चीज की आज भी जरूरत हैं ऐसा करने से मेरा विश्वास है कि कुरप्शन को कम करे सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पर इन चीजों को भी असर पडऋता है कि लोगों के मान के अन्दर काम करने की भावना है या वह डर से काम करते है या वइ सिलए काम करते है कि उन्हैं कुछ न कुछ रिवार्ड मिले जिससे उनका मान बढे। जब तक लोगों में डर न हो या उनको कोई प्रोत्साहन न मिले वह ठीक काम नही करते। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोहिब्शन से भी बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि ज्यादातार कत्ल शराब पीने से होत`है जिन से जरायम के ओंकड़ों में वृद्धि होती है। आमतौर पर लोहड़ी तथा दूसरे त्यौहारों पर लोग शराब ज्यादा पीते है और जरायम में इजाफे का कारण बनते है। आप ने देखा होगा कि सिक्खों के गांवोम में जह जयादातर लोग शराब पीते है।, हर रोज कोई न कोई कत्ल होता ही रहत है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोहिब्शन से बहुत भारी संबंध है। सरकार को जो प्रोहिब्शन से आमदनी`ाती ै उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नही देना चाहिये। सरकार ने कभी यह भी देखा है कि उस परि पब्लिक का कितना पैसा खर्च होता है। मेरे ख्याल में शराब पर जितना खर्च होता है। वे शायद स्टैट के बजट से भीजयादा हो। सरकार को पब्लिक मारेलिटी को भी देखना चाहिये। मै ता कहूगा कि सरकार को प्राहिब्शन लागू करने

के लिये कोई डेट फिक्स करनी चाहिये। शराब से लागों को फायदा नही होतौ। अलबत्ता उनकी सेहत खराब होती है। मैडिकल एस्कपर्टस ने भी इस बात को माना है शराब से लागों को कोई फायदा नही होता बल्कि इससे सेहत का पबुरा असर होताह है। चीफ मिनिस्टर साहिबन ने कहा है कि एक स्टेट या एक जगह पर प्राहिब्शन करने से कोई फायदा नही क्यों लोग दूसरे सूबों से शराब को स्मगल कर लेगं। यहा कोई आर्गूंट नही है। आप को प्राहिब्शन लागू करनी ही पड़ेगी। ऐसा करना भी ाचाहिये। कांस्टीच्यूशन ने भी इस बात के लिय लिखाहुआ है। ऐसा करने से सरकारे को जो हनुक्सान होगा वह दूसरे ढंग से वसूल कर सकती है।

आज कल एडमिनिस्ट्रेशन मे रैड टेपिज्म भी बहुत पाई जाती है। किसी को भी आगे सरकने नही दिया जाता। लोगों में यह ख्याल पाया जाता है कि जितने केसिज में डिले की जायेगी उतना पब्लिक तंग होती और केसिज को जल्दी निकलवाने के लिये कुछ न कुछ जरूर देगी। इस टैण्डैसी को जरूर चैक रकन चाहिये।

सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के बारें मे लोगों को तकलीफ है। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन आम दुकानदारों के जरिये से होती है। और दुकानदार उसकों खुल्मखुल्ला ब्लैक में बेचते है। लेकिन बी.डी.ओज. के जरिये जो परसैटैल सीमेंट की डिस्ट्रीब्यूट होती है वह तो लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा लोगो को

पता ही नही चलात कि मार्किट में सीमेंट कब आई है। सरकार को चाहिये कि यह सैट्रल गवर्नमेंट को कहे कि सीमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आफिशिल्ज के थ्रू कराने का तरीका शुरू करेंट इससे लागों की तकलीफ कम हो सकती है। ईटों की कीमत भीा आजकल भाव से ज्यादा वसूल की जाती हे। इस मामले में भी काफी ब्लैक चली हुई है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

व्हीट प्रौक्सोरमेंट के बारमें मे यह सभी मेम्बरों ने कहा कि किसानों को अनाज की कीमत कम मिली है और उनके अनाज की कोई कदर नही की गई। लोग यह कहने पर मजबूर हो गये है कि राव साहिब की सरकार भी अच्छी थी क्योंकि उस वक्त उन के अनाज की कदर होती थी और उन्हे अच्छे दाम मिल गये थे। यह भी देखने में आया है कि उनका अनाज दस दस दिन तक सड़ता रहा मगर वह न उठाया गयाहै मैक्सीकन व्हीट जो बी की डिस्टीब्यूशन के लिये अच्दे दाम पर खरीद कर बाद में ज्यादा दाम पर बेच दिया इसमें सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के आदमियों ने भ उन का पूरा साथ दिया। इस तरह से जमींदारों को करोड़ों का नुक्सान हुआ।

शुगर की डिस्ट्रीब्यूशन में भी देहातों और शहरों में फर्क रखा गया है। देहातों मं चीनी कम दी जाती हऔर शहरों में ज्यादा। सरकार को सब लोगों को बराबर समझना चाहये और इस सिलसिलें मे कोई फर्क नही रखना चाहिये।

प्राइसिज को भी सरकार को स्टेबेलाइज करना चाहिये। यदि आप तीस साल की फिगर्ज देखें तो आप को पता चलेगा कि फसलों के वक्त अनाज की कीमत कम होती रहीहै और उसके बाद ज्यादा। इससे उन लोगों को फायदा हुआ जिन्होनै किसानों से अनाज खरीद कर जमा कर लिया और बाद मै बेचा। इससे भी जमींदारों को घाटे में रहना पड़ा।

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारें में सबकी इच्छा है कि यह हरियाणे के लिये अलग हिसार में होनी चाहिये। इस बजट में भी सरकार ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिये तीस लाख रूपया रखा। अज कल जो खर्च उस पर हेाता है। उसके मुताबिक हमें फायदा नही मिल रहा है। अगर हरियाणे के लिये अलग ऐसी यूनिवर्सिटी कायम हो जायेगी तो यह अच्छी बात होगी।

करनाल में जो आई.ए.डी. प्रोग्रा चल रहा है इससे खेती को बढ़ावा मिला है और उससे यील्ड मं भी बड़ा भारी फर्क पड़ा है। रिसर्च के साथ साथ एजूकेशन और एक्सटैशन भी जरूर होनी चाहिये। रिसर्च को किताब में ही बंद रखा जात है तो उससे कोई फायदा नही हेाता। एग्रीकल्चर में जा रिसर्च हा रही है उसको किसानों तक भी पहुंचना चाहिये ताकि वह उससे फायदा उठा सके और अपनी पैदावार को ज्यादा बढ़ा सकै।

लैड मार्गेज तथा को–आप्रेटिव बैक्स और सैट्रल एग्रीकल्चर रीफाइनान्स से काफी मदद मिली है। जिससे किसानों

को काफी बढ़ावा मिला है और उससे से काफी कुछ तरक्की हो रही है।

फिर आज कल यह शिकायत है कि ट्रैक्टर ब्लैक में मिलते है। आज कल तो मैकीनाइजेशन हो रही है। ट्रैक्टरों के बगैर तो काम चलेगा ही नही इसलिए कोई न कोई कारखाना लगाना चाहिये। सुना था कि नीलाखेड़ी मं 2 करोड़ रूपए की एक स्कीम ट्रैक्टर के कारखाने के लिये बनाई गई थी मगर अब वह ठप्प सी हो गई है। जहां तक ट्रैक्टरों की एबेलेबिलिटी का ताल्लुक है, मै समझता हूं कि गवर्नमैंट को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

एरियल स्प्रे का जिक्र किया गया। मै समझता हूं कि जहां पर कपास के कम्पैक्ट ब्लाक होते है वहां पर एरियल स्प्रे सम्भव है पैचिज पर हवाई जहाज से स्प्रे नही हो सकता।

फर्टीलाइजर क लिये 3 करोड़ की रकम रखी गई है यह एक अच्छी बात है। सैटलमैंट की बात कई मेंम्बरों ने दोहराई है। उसमं सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया जाना चाहये था कि कितने परसै।ट लैड रैवेन्यू में इन्क्रीज होगी तो उससे जमींदार आश्वस्त होता है। किसानों की हालत तो हमैंशा से ऐसी चली आती है कि वे उगाही नही दे सकते थे पहले जमान`में थानों में ही उनकी जिन्दगी गुजर जाती थी। तो अब अगर वह नमक रोटी खाते खाते कुछ अपनी दशा सुधार पाए है, तो उनकी को

बिगाड़ना नही चाहिये खबरें है कि रेट 30 या25 पर सैंट तक मामला बढ़ाया जाए, मै समझता हूं कि यह बहुत ज्याद हैं कई जगह पटवारी भी करप्शन करने में लगे हुए है। वह कहते है कि हमें कुछ दो तो हम तुम्हारें कुछ रेट कम फिक्श करवाएंगे और नही तो ज्यादर करवादेगें। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

जहा तक को–आप्रेटिव स्कीमों का ताल्लुक है। वह पोलीटिकल कंसीड्रैशन की वजह से ड्राप नही करनी चाहिये। करनाल में ए को–आप्रटिव स्कीम बनी थी मगर पता नही उसका क्या हुआ। जिला करनाल में जहां पर खादर का इलाका है वहां पर गन्ना की पैदावार अच्छी हो सकती है, उस तरफ बढ़ावा देना चाहिये।

देहातों मे जो डिवैल्पमैंट हो रही है उसमें एक प्लैनिग होना चाहिये कि कैसे एनीमल शैडज, कैसे हाउसिज, और किस तरह गलियां वगैरह का निकास हो इस सबक लिये पंचायते के पिस नक्शे प्रोवाइड किए जाने चाहिय। देहात में मछलियों की जो पैदावार है वह बिल्कुल सस्ते में ही लोग ले जो है, जब कि शहरों मे ंवही जाकर बहुत मंहगी बिकती है।

सड़कों की मुरम्त करवाने और उनके बनवाने में कम्पलसरी लेबर लेना चाहिये। इसके लिये सरकार को मजबूती से काम करना होगा। रेलों की लाइनों न बनने से लागो का बहुत

भारी नुकसान हुआ और सड़के न बनने से तरक्की रूकी है। इसलिए इस तरफ विशेश ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री बनारसी दास गुप्ता (भिवानी): माननीय सभापति जी, दो दिन तक बजट पर बहस होती रही है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण विभागों की ग्रांट्स पर बहस हा रही है। जहां तक जनरल बजट का ताल्लुक है, मैने बहस सुनी और उन बड़े पालियामेंटीरियन्ज की स्पीचों को सुना जो इस बात का दावा करते है। कि उनका पालिटिकस मे बड़ा भारी तजरूबा है, और सूझ बुझझ बहुत ड़ी चढ़ी है। हमारे जन संघ के नेता डाक्टर मंगल सैन के भाषण को भी 40 मिनट तक सुना जो छाती तान कर कह रहे थे कि मै बहुत भारी विधायक हूं मगर उन्होने बजट के सिलसिलें मे एक बात भी तथ्य की नही कही। कुछ बातें मुझ को दृष्टिगत कर कही और कुछ मुख्य मंत्री को मुखातिब करके कही और सारा समय इन्ही बातें में निकाल दिया। अगर डाक्टर मंगल सैन जैसे विधायक कुछ रचनात्मक सुझाव देते तो हमरे प्रदेश को कुछ लाभ होता आखिर में मै आज के विषय पर आता हूं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ग्रांट पेश की गई। इसमे कोई सन्देह नही कि प्रशसन में एफीशेसी बहुत नही है। प्रशासन बहुत खर्चीला है, प्रशासन में लाल फीताशाही है। मै मुख्य मंत्री महोदय से और सरकार से यह

निदवेदन करूंगा कि प्रशासन को उन्नत करने के लिये और जनता को शुद्ध प्रशासन देने के लिये पूरा चेष्टा की जाए। और इसके विषय में विरोधी दल की तरफ से भी पूरा पूरा सहयोग मिलना चाहिये। केवल नुक्ताचीनी करने से कोई बात पूरी नही`ाती। मै मलिक मुख्त्यिार सिंह तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, वह इस वक्त सदन मै बैठे नही है, डाक्टर मंगल सैन से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें पहुंचा दे। उन्होने कहा थ कि उन की राय में भ्रष्टाचार प्रशासन मे ंउस वक्त नही चल सकता जब कि उसकी पुश्त पर किसी वजीर या किसी नेता का हाथ न हो। मै पूछना चाहता हूं कि राव साहिब के जमान`मं जब कि सरकार उनके इशारे पर चलती थी तो उनकों मालूम होगा कि इकिस वजीर का हाथ होने पर ही भ्रष्टाचार चलात है। मै यह निवेदन करताहूं कि भ्रष्टाचार चाहे किसी के जमाने में हो मगर उसको समाप्त करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिये। ओर हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने केलिये कुछ ठोस कदम उठाए जोए ताकि तनता के ऊपर से कुछ बोझ हल्का हो। जो पैसा इस तरफ से बचेगा उसे विकास के कामों पर खर्च किया जाए। (इस समय उपाध्यक्षा ने आसन ग्रहण किया) जब से यह सरकार बनी है, उपाध्यक्ष महोदया आपको भी पता है कि तबसे कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे है जिससे प्रशासन इतना खर्चीला न हो ओर इतना बोझिल नहो कि जनता इसको सह न सके।

अभी इस हाउस में डिमांड रखी गई कृषि के सम्बन्ध मं कोई संदेह नही कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रांत है और इसमें भूमि पर कृषि को बढ़ावा देने के लिये जितना ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए उतनी ही खुशहाली आएगी। हमें यह बात सुन कर बड़ी खुशी होती है कि इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई और टीचा निर्धारित किया गया था उससे भी अधिक हुई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे विश्वास है कि यदि छोटी छोटी सिचाई की योजनाओं को पूरा ध्यान दिया जाए औ जिस इलाके में भूमि मिलता वहां पर पानी दे दिया जाए तो पैदावार बहुत बढ़ उसकती है। मै खास तौर पर से भिवानी की तहसील का जिक्र करता हूं। वहां ज्यादा भाग जमीन का ऐसा है जहां पानी नही मिलता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ुरानी रजनीतिज्ञ है, आपको पता होगा कि जब पंजाब के न्दर यूनियनिस्ट बसरकार थी तब सर छोटू राम जी ने आश्वासन दिया कि जब भाखड़ा का बांध बांधा जाएगा तो उससे जिला हिसार की भिवानी तहसली को दूध की मकक्षी की तरह निकल करक बाहर फैंक दिया गया, और इसकी एक इंच जमीन को भी भी पानी नही दिया गया। मै सरकार से यह निवेदन करूंगा कि भिवानी तहसील को खेती के लिय पानी दिया जए। जहा नहर का पानी ले जाया जा सता है वहां नहर का दिया जाए और जहां नहर का पानी नहल लग सकता वहां पर ट्यूबवैल लगा कर खेतों की सिंचाई की जाए। तहसली ीिवानी की जमीन बहुत उपजाऊ हैं लोहारू का इलाका ओर महेन्द्रगढ़ जिला का वह इलाका जहां मीटा पानी निकलता है वहां पर किसानो ंने कुछ

ट्यूबवैल लगाए है और वह अपने खेतों में अंगूर तक पैदा कर रहे हैं मै निवेदन करूंगा कि लोहारू ओर महेन्द्रगढ़ के उन इलाकों में जहां पानी कड़वा है अगर बिजली के जरिए पानी पहुंचाया जाए तो वहां खुशहाली आ सकती है। इसलिए मै प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार परइतना प्रभाव डालें कि वह उस इलाकें पर अधिक से अधिक खर्चा करें जो आज डिमाड्ज पैश की गई है इसमें सहकारिता का भी जिक्र है। सहकारिता का एक बहुत अच्छा आंदोलन है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो लोग डत्रे बडत्रे खेती के काम कर सकते है। किसान जो है वह अकेला अपने लिये सारे साधन पैदा कर सकता लेकिनसहकारिता के द्वारा सरकार से अच्दे अच्छे साधन लिय जा सकते है और खेती अच्छी हो सकती है। यह बात उद्योग धंधों के सम्बन्ध में भी की जा सकती है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सहकारिता में ड़ी कुनबापर्वरी चलती है, 10, 10 या 15, 15 आदमी एक ही कुनबे के मिल कर को–आप्रेटिव सोसाइटी बना लेते है जिस पर कि एक आदमी का अधिकार होता है भिवानी सैट्रल को–आप्रेटिव बैक की मै आपको मिसाल देता हूं, उस पर एक ही आदमी का कब्जा है ओर उसबैंक मे लाखों रूपए का गबन हुआ है जिसकी कि अब जांच पड़ताल की जा रही है। मेरा कहने का भाव यह है कि इस सहारी मूवमैंट का दुरूपयोग होता रहा है और इस में चंद आदमी ही फायदा उठाते रहे है। इस में यदि सुधार किया जाए ता असल फायदा उठाया जा सता है। मै आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जहां तक उद्योग धंधो का

सम्बन्ध है इनकों पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिये। देा ही साधन है खेती और उद्योग धंधे जो किसी भी प्रदेष को खुशहाल बना सकते है। लेकिन हमारे हरियाणा में इन दोनों की बड़ी भारी कमीहे। इकी ओर ध्यान दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब ज्वायंअ पंजाब था तो भिवानी ओर भिवानी नगर व्यापार क लिहाज से सारे प्रांत मे ंदूसरे नम्बर पर था और अमृतसर पहले नम्बर पर था लेकि आज वहां पर बेराजगारी फैली हुई है ओर पुराने समय की जो वहां कपड़े कि मिलें है उनकों छोड़ कर और कोई उद्योग धंधा नही है। जिससे लोगो को रोजगार मिल सकें। वहां से तमाम राजस्थान को माल स्पलाई हो सकता है। इसलिए मै सरकार को प्रार्थना करूंगा कि भिवानी को औद्योगिक विषय से फोकल केन्द्र बनाया जाए। मलिक मुख्तियारसिंह जी ने कहा ाि कि सोनीपत क अन्दर एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा रही है जिससे काफी जमीनबरबाद होगी। मै उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वह पसन्द नही करते कि ऐसी बस्ती वहां पर बनाई जाए तो मै स्वागत करता हूं अगर वह बस्ती भिवानी में बना दी जाए। वहां पर हम जमीन भी देने के लिय तैयार है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, भिवानी के बड़े बड़े मालदार लोग दूसरे प्रदेशों मे बड़ी बड़ी मिले चला रहे हें अगर उनको भिवानी में सुविधाएं दी जाएं तो वह इधर अट्रैक्ट हो सकते है और अपनी तमाम पूंजी लगर कर हरियाणा की तरक्की कर सकते है।

श्री फतेह चन्द विज: डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या टाइम की पाबन्छी इधर ही लगती है या कि उधर भी है?

उपाध्यक्षा: नही जी दोनो तरफ है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर यह कहा गया है कि हरिजनो ंके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है लकिन यह बात अवश्य है कि जितनी सुविधाएं उनकों ऊंचा उठाने के लिये मिनली चाहिए थी उतनी अवेलेबल नही है। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलते दी जाए। इस अवसर पर मै यह निवेदन करूंगा कि आपका जो अैनंसी एक्ट है उसमे ंकोइ मुनासिब तरमीम करके मुजारों की प्रोटैक्शन दी जाए ताकि वह जमीन से दिल लगा कर काम करें। और अनाज की पैदावार बढ़ा सके। बस मै इता कह कर स्थान लेता हूं।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मै यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा की जो भाषा हिन्दी है मेम्बर साहिब को उस में बोलना चाहिये क्योंकि जिस भाषा में वह बोल रहे है वहां किसी की समझ मे ंनही आ रही है। अगर वह नही चाहते हकि कोई उन्हे समझे ओर वह हिन्दी में बोलना

नही चाहते तो इसका कोई फायदा नही। यही समय दूसरों को दिया जाए।

उपाध्यक्षाः सदन में जो मेम्बर जिस जबान में बोलना चाहे बोल सकता है।

आवाजेः गलत है गलत.....(शोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंअ आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै आप का ध्यान मेंयह बात लाना चाहती हूं कि जा कुछ मेम्बर साहिब बोल रहे हैं उसका उनके पास कोई सबूत भी है या यूं ही अखबारी बातों की बिना पर ऐसा कर रहे है। अखबारों में कई किस्म की बातें आती है कई अथैटिक भी होती है और कई बेबुनियाद भी होती है लेकिन उको आधार मान कर हाउस में ऐसी बात करना ठीक नही है। जहां तक सिक्ख धर्म की बात है चाहे कोई केस रखता है या नही रखता लेकिन इसका यह मतलब नही कि हम उनके गुरूओं को इज्जत नही करते हम सब एक ही स्टाके से है। ऐसी भड़काने वाली बातें जिनका कोई सबूत न हो नही करनी चाहिये।

उपाध्यक्षा: मै मेम्बर साहिब से रिक्वैस्ट करती हूं कि जा बात हाउस में कही गई है उसके बारें में वह बात कर सकते है लेकिन जो बात इधर उधर की है और जिसका हाउस से कोई सम्बन्ध नही है उसका जिक्र वह यहां नही कर सकते।

Chief Minister: On a point ofr Orderm Madam. The hon. member should speak on General Adminsistration and other Demands before the House. This is not a place for propagating regligion.

Ch. Chand Ram: On a point of order. Madam. The grouse of th hon. Member, is that whatever appeared in the press, shoud have been contradicted by the Chief Minister if it was not correct, as he is the Head of the General Administration. In the absence of that, the hon. Member has every right to critizize the Administraton.

उपाध्यक्षा: जहां तक अखबारों का सम्बन्ध है उनमे कई किस्म की बातें आती है कई ठीक भी हो सकती है और कई गलत होती है ओर कई दफा उनकी कंट्रडिक्शन कद दी जाती हैं लेकिन दफा हर अखबारी बात की कंट्रडिक्शन ही नही भी हो सकती।

चौधरी चांद रामः बड़ा रैलेवैंअ प्वायंअ है। और इसे बडे कामली और एंज कसटोडियन आफ दी हाउस आप सुनेा और देखें। कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक किसी कम्युनिटी के सैटीमेंट ्स से है अगर उसका चर्चा अखबारों में हाता है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने एसा कहा है तो उसका चीफ मिनिस्टर साहिब को नोटिस लेना चाहिये और अगर वह गलत है तो उसकी तरदीद करनी चाहिये। इनसके पास जा पब्लिक रीलेशन का महकमा है आखिर वह किसलिये है मै भी मिनिस्टर रहा हूं और मुझ पता है कि उस महकमं वाले कटिग भेजते है और ऐसी बातें। डियू नोटिस लिया जाता है चाहे वह गलत हों या सही हो। इसलिये मै चीफ मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि उनको इसकी तरदीद करनी चाहिये ओर अगर पहले तरदीदी नही की गई हो तो मैम्ब्र साहिबा का हक्क है। कि वह वहा उस बात को सरकार के नोटिस मे ंआए। अगर यह बात गलत है तो अब वह उठ कर इसकी तरदीद कर दें।

मुख्य मंत्रीः हर ऐरी गैरी बात कि जिसका कोई सिर पैर न हो तरदीद नही हो सकती.....(शोर).....

खान अदुब्ल गफ्फार खांः आन ए प्वायंअ आफ आर्डर, मैडम ! मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ है कि चौधरी चांद राम साहिब

यह फरमाते है कि चीफ मिनिस्टर साहिब को इस की तरदीद करनी चाहिए थी। ऐसा बेहूदा बात जो कभी चीफ मिनिस्टर साहिब की जवान से नही निकल सकती जो कि इन्ते जिम्मेदार आदमी हो जिनके पसा सारे सूबा का नजमोनकस हो उनके साथ अगर ऐसी बेहूदा बात मनसूब की जाए मै समझता हूं कि चीफ मिनिस्ट साहिब हकबजनाव थे कि उन्होने उस बेहूदा बात की तरदीद नही की। मै पूछता हूं कि क्या मेम्बर साहिबा का फर्ज नही बनता था कि जिस बात का आज वह यहां जिक्र कर रहे है उसके बारमें मैं यह चीफ मनिस्टर साहब से बात करते और उन से पूछते.....

उपाध्यक्षा: खान साहिब आप स्पीच न करों।

खान अब्दुल गफ्फार खां: मै जनाब प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हू और यह बता रहा हूंकि क्या यह उस मैम्बर का फज्र नही था कि वह चीफ मिनिस्टर साहिब के पास जाते और कहते कि क्या आपने एसी बात कही है?

मुख्य मंत्री: वह मुझे मेरे कमरे में मिल थे और इस बारेमें उनकी मेरे साथ बात हो चुकी है लेकिन अब फिर यहां पर कहने लग पड़े है।

खान अब्दुल गफ्फार खांः लो अब आप ही सुन लो। यह तो हाउस में कहलवाया गया है ताकि चीफ मिनिस्टर साहिब को बदनाम किया जाये। हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नही कर सकते। जब वह उनसे पहले बात कर चुके थे तो फिर यहां पर बात करने की क्या जरूरत थी। जब वह उनसे पूछ आए है ओर वह उसकी तरदीद कर चुके है और दोबारा चहां आकर उस बात को उठाते है तो क्या आप इसकी इजाजत देंगी? अगर आप ऐसी बात की इजाजत देगी तो मै समझा हूं कि हाउस का डैकोरम प्रैस्टीज जाया हो जाएगी।

उपाध्यक्षाः मुझे डैकोराम कायम रखना आता है वह इस बात का फिकर न करे। यहां हर मेम्बर को बोलने का अधिकार है और किसी का अधिकार छीना नही जाएगा। यहां पर अगर कोई बोल सकता है है तो उसकी कंट्राडिक्शन हो सकती है और प्वायंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है जैसा कि आपने उठाया है और उसे सुना गया है।

Khan Abdul Ghafar Khan: What is your ruling, Madam, on this point. What the hon. Members has said on the floor of the House, is, altogether, baseless and unfounded and

he should not have said this. He cannot raise such things as a matter of right.....

Deputy Speaker: I have heard your point of order. You need not make speech on this point.

Ch. Chand Ram: Madam, this is very important aspect of the administration and the hon. Member should be allowed to speak on it.

आवाजे: क्या प्वायंट आफ आर्डर था या स्पीच थी?

श्री मती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै कहना चाहती हूं कि कोई भी प्रोगेगंउा के तौर पर और प्लेटफार्म क तौर पर इस सदन को इस्तेमाल नही कर सकता और नह ही कोई धामिक प्रोवोकेशन करने के लिये बोल सकता है। इसलिए वहा उस सब्जैक्ट पर बोले जो इस वक्त हाउस के सामने है।

उपाध्यक्षा: मै आनरेबल मेम्बर साहिब से रिक्वैस्ट करूंगी कि वह डिमांड पर बोले।

उपाध्यक्षा: आप रैलेवैंट बोले।

मुख्य मंत्री: आन एं प्वायंअ आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै पूछना चाहात हूं कि मेम्बर साहिबा किस डिमांड पर बोल रह`।।

उपाध्यक्षा: मै आनरेबलक मेम्बर साबि को सिर्फ डिमांड पर ही बोलने दूंगी और इनैलेवट नही होनी दूंगी। आप जनरल एडमिनिस्ट्रशन या बजट की दूसरी डिमांड परबोल सकते है। मै स्ट्रिक्टली इस चीज पर अमल रूंगी। इसलिए मै मैम्बर साहिब से कहती हूं कि वह अपनी स्पीच में रैवेवैसी रखे।

Ch. Chand Ram: May I know, Madam, Deputy Speaker, what prevents the hon. Member to mention these things? Today we are discussing general administration which includes all these things. Pay and other allowances of the Chief Minister and others are included in the general administration and the hon. Member by his speech is criticising the administration of the state.

उपाध्यक्षाः चौधरी साहिब, मै यहां पर बैठी हुई हूं, सब कुछ जानती हूं कि किस पर बोलना चाहिये और किस पर नही। सरदार साहिबा, आपका टाईम हो गया है मैने मिनिस्टर्ज का टाईम काट कर मेम्बर्ज को दिया है इसलिए आप बैठ जाए।

Depputy Speaker: Order, plese.

Ch. Chand Ram: Madam Deputy Speaker, General ADministration includes all these thing.....(Noise).

Malik Mukhtiar Singh: Madam, the hon. Member, Sardar Teja Singh is quit relevant.

श्रीमती चन्द्रावतीः चौधरी साहिब ने जो डिप्टी स्पीकर साहिबा की शान के खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल किये है वे उन्हें विदड्रा करने चाहिये।

चौधरी चांद रामः मैने डिप्टी स्पीकर साहिबा के खिलाफ कुछ नही कहा। I have utmost respect ofr the Chair. But the Chair should see what general administration means. What the hon. Membe, Sardar Teja Singh, is saying are important

observatins. They concern the House as well as the Members. He has every right to speak on matters covered by general administration.

उपाध्यक्षाः आर्डर, प्लीज ! यह देखना मेरा काम है कि आया वे जनरल डिमांड्ज पर बोल रहे है या नही। (व्यवधान)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिबा, आपकों शायद याद होगा, पंजाब में जब दास कमीशन एप्वायंट हुआ था तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में मैल–प्रैकिटसिज हुई थी, उनकी तहकीकात हुई थी इसलिए यह मामला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। आप तेजा सिंह जी को बोलने दीजिए, हाउस में वैसे ही गरमागरमी आ गई है। (व्यवधान)। अगर आप कूल हैड से सोचे तो यह सारी चीजें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मे आती है।

उपाध्यक्षाः आनरेबल मेम्बर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पर बोले, तो मै आपको पूरी तरह सहयोग दूंगी।

Chief Minister: Madam Deputy Speaker, the hon. Members has said very undesirable thing. The is speaking most derogated for the whole of Haryana. He should not be allowed to say such things rather he should be named.

Shri Daya Krishan: Madam, Deputy Speaker, all these words are an insult to the whole of Haryana and therefore, they should be expunged from the proceedings of the House.

उपाध्यक्षा: मै इन लफ्जों को एक्सपंज कर देती हूं।

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये जितनी भी तकरीर है इसमें ये यह लफ्ज ही नही बल्कि सारी की सारी स्पीच को एक्सपंज कर देना चाहिये।

उपाध्यक्षा: मैने कह दिया है चौधरी रण सिंह, आप अपनी स्पीच शुरू करें। (लेबर मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री श्याम चन्द: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे टाइम नही मिला, हर एक मेम्बर जो बोलना चाहे, को टाइम मिलना चाहिये।

उपाध्यक्षा: आपकों ऐप्रोप्रियेशन बिल पर सबस से पहले टाइम दिया जाएगा।

उपाध्यक्षा: आर्डर प्लीज। आप बैठ जाए, आपका टाइम खत्म हो गया है।

Walk Ouu

(इसके बाद पहले तेजा सिंह जी वाकआउट कर गये ओर बाद मे बाकी युनाइटिड फरंड वाले मैम्बर वाक आउट कर गए)

DEMNDS FOR GRANTS (RESUMPTION)

श्री मंगल सैनः उपाध्यक्षा महोदयाा, श्री श्याम चन्द्र जी ने पूछा था कि उन्हे बोलने की इजाजत दी जाए। आपने फरमाया कि उन्हें एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिय सबसे पहले टाइम दिा जाएगा। मै ाअपके जाना चाहता हूं कि जिस दिन एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाएगा उन दिन क्या यह जरूरी है कि आप ही कुर्सी पर बैठी होगी?

उपाध्यक्षाः शायद। यदि मै न भी हूंगी तो जो बैठा होगा उनसे कह दूंगी।

श्रम मंत्री (चौधरी रण सिंह): उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुषी हे कि इस हाउस के नए कांग्रेसी तथा विरोधी दल के सदस्यों ने कृषि के संबंध में बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिये। पुराने मैमबर्ज तो आपस में ही उलझते रहे परन्तु बहुत से नए मेम्बर बहुत अच्छा बोले है। आपकी मारफत डिप्टी स्पीकर रसहिाबा, मै हाउस को यकीन दिलानाचाहता हूं कि सरकार इन सब सुझावों पर गौर करेगी। कई साथियों ने डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिस्ट्रिब्यूशन आफ सीड के मुताल्लिक बाते की कि सीड वक्त पर नही मिलता, देरी से मिला है और कई दफा डिफैक्टिव मिला है। इबस बारेमें मै अर्ज करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल के लिये हमने इस बार मई और जून के महीनों में 1,200

क्विंटल मक्की का बीज तकसीम किया है, जो कि बिजाई से काफी पहले का समय था और न ही उसके बारेमे मे अभी तक कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। हाइब्रिड बाजरे मै देसी बाजरे का बीज भी मिलया गयाहै। मै तो समझता हूंकि हाइब्रिड बाजरे के बीच की थैली में जो नैषलन सीड कारपोरेशन से खरीदा जाता है देसी बाजरे का बीज मिलाना सम्भव ही नही क्योंकि उस पर सील लगी होती है लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई सालि बात बताएगा ता उसके मुताल्लिक इन्क्वायरी कराई जा सकती है।

ट्रैक्टर्ज की तकसीम के मुताल्लिक कई सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये है ओर मै ईमानदारी से महसूस करता हूं कि हरियाणा के अन्दर वास्तव में ही ट्रैक्टर्ज की किल्लत है और जब तक इनकी डिमांड को हम पूरा नही करते तब कि किसान अच्छी तरह से काम नही कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हरियाणा के नए विधायकों ने असली मायनों में यह महसूस किया है कि हम हरियाणाकी उत्रति के रास्ते पर ले जा सकते है जबकि कुछ सीनियर मेम्बर आपस में उलझते ही रहे। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने, डिप्टी साहिबा, आप को याद होगा, हमें यह नारा दिया था कि हम अनाज की लिफाफों में बन्द करके बेचेगे और मककी का भाव अंगूर के बराबर करेंगे। लेकिन हम तो ऐसा नही करना चाहते। हम तो पूरी कोशिश के साथ और पूरी शक्ति लगाकर यह करेंगकि पैदावार इतनी बढ़ जाए जिससे

हर किसान का मकान, कोठे आदि बनाज से भर जाएं और उसे हर प्रकार की सहूलियते मिल सकें मै तो हरियाणा के माथे पर कलंक समझता हूं यदि इसे, इसकी जमीन अन्य प्रांत के मुकाबिले अच्छी होने और इसके किसान के महनती होने के बावजूद भी गैकवर्ड कहा जाए। डिप्टी स्पीकर सहिबा, वह दिन दूर नही जब यह सरकार इस कलंक को धो देगी। (प्रशंसा) ट्रैक्टर्ज के बारें में मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बोर सरकार का पूरा ध्यान है। 1967 में हिन्दूस्ताान में कोई एक हजार ट्रैक्टर्ज इमपोर्ट हुए थे और इन में से अकेले हरियणा को जोकि एक छोटा या पद्रेष है 200 ट्रैक्टर्ज आए थे। सितम्बर में एक हजार ट्रैक्टर्ज ओर आने वाले जिनमे से 200 ट्रैक्टर हमें फिर मिलने की उम्मीदहैं इसके अलावा हम प्राईवेटली भी 250 ट्रैक्अर फरीदाबाद की ट्रैक्अर बनाने वाली एसकोर्ट कम्पनी से लेने की कोशिश कर रहे है और मुझ उम्मीद है कि इस तरीके से लोगों की ट्रैक्टर्ज की मांग को हम पूरा कर सकेंगे।

श्री फतेह चन्द विजः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक प्यायंट आफ आर्डर है। मै कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ट्रैटर्ज की सप्लाई में इस दफा भी पहले की तरह धांधली होगी और अबकी बार भी एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा सप्ताई किये जाएंगे?

उपाध्यक्षाः विज जी, यह क्या कोई प्वायंट आफ आर्डर है यह तो आपने प्रश्न पूछा है। आयंदा के लिय मेरी सब मेम्बर साहिबान से प्रार्थना है कि वे इस तरह के प्रश्न किसी दूसरे मेम्बर की स्पीच के बीच मे ने पूछा करें।

मलिक सतराम दास बत्राः उपाध्यक्ष महोदया, मै आपके द्वारा कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि स्पयेयर पार्टस का क्या किया जाएगा?

उपाध्यक्षाः मै अभी कह कर हटी ही हूं कि इस तरह से सप्लीमेंटरी आप मत करिए क्योंकि यह कोई क्वैश्चन आवर नही है। मिनिस्टर साहिबा आपने आप सब बातों का जवाब दे देगे।

श्रम मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदया, मिस्टर बत्रा ने अपनी स्पीच के दौरान बड़ी सराहनीय बातें कही, इसमे कोई शक नही। चाहे वे अपोजीशन से ही है मुझ उन की कई बातें बड़ी पसन्द आई । स्पेयर पार्टस वाला इनका बहुत अच्छा सुझाव है। ट्रैक्टर्ज जब हामरे यहां आ जायेगे ता उनकी मुरम्मत का इन्तजाम करना भी बहुत है। इसके लिए मै इन्हे विश्ववास दिलाना चाहता हूंकि

मुरम्मत के लिये भी सरकार अवश्य इन्तजाम करेगी। एक साथी ने डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां कहा कि हिसार के गवर्नमैंट फार्म में बड़े डिफैक्टीव ट्रैक्टर्ज है और उनकी वजा से फार्म को बहुत नुक्सान होता हैं मै इस बारें में सदन को बता दना चाहता हूं कि यह बात ठीक नही है क्योंकि 40 ट्रैक्टर्ज तो अभी अभी नए भेजे गये है जो कि मेरी सूचना के अनुसार बिल्कुल परफैक्ट आर्डर में है। इनके अलावा यदि कुछ ट्रैक्टर्ज वाकई आउट आफ आर्डर पर होगे तो उनको ठीक करवाने या री–प्लेस करने के लिये कदम उठाए जायेंगे।

मेजर अमीर सिंह और बाबु दया कृष्ण जी की भी कई बातें मुण बड़ी पसन्द आई जिला जींद और महेन्द्रगढ में बोरिग आपरेशनज का भी इन दोनों ने जिक्र किया। जींद के बारें में तो मै नही समझता कि उनकी बात दुरूस्त है क्योंकि वहां के दो गांव खूरजा खेड़ा और खाना खेड़ा में हमअीाी टैस्ट बोर करवा चुके है। इनके अलावा दो ओर गांव हम वहा सीलैक्ट करने जा रहे। बाकी महेन्द्रगढ़ जिले के मुताल्लिक जैसा कि मेजर अमीर सिंह जी ने कहा है कि उनकी यह बात खास तौर पर ध्यान रे खीज जायेगी, वाजिब बात है। जैसा मुनिसिब होगा हम इस मशीन का इन्तजाम करने की कोशिश करेंगे। परन्तु डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै आपके जरिए हाउस को बताना चाहाता हूं कि हमारे पास रिंग मशीन की बड़ी किल्लत है। और ये मशीनें मंहगी बहुत मिलती है। हमारे पास ये बहुत पुरानी मशीनों है, नयी हम खरीद नही सकते

है जब भी हमारे रिग मशीन अवेलेबल होगी हम महेन्द्रगढ़ जिले में इस मशीन को भेजने का प्रबन्ध करेंगे।

कई भाईयों ने यहां ट्रैक्टरों के बारें में कहा कि ब्लैक में अवलेबन है वैसे ये एजैन्सी से कन्ट्रोल से नही मिते है। अगर किसी की डैफिनिट पता है और हमारे नोटिस में लायेंगे तो हम इस बात की जरूर इन्क्वायरी करायेगे।

एक बात मै लैड रक्लेमेशन के बारें मे कहना चाहता हूं। यह बात बहुत मौजूं है। जब तक हम बंजर जमीन को रीक्लेम नही रकेंगे तब तक हम पैदावार को नही बढ़ा सकते। अनाज की बढ़ौतरी के लिय हमं इस तरफ ध्यान देना चाहतु जरूरी है। तो यह सुझाव भी ध्यान में रखा जायेगा।

कई भाईयों ने फर्टेलाइजर के मुतालिलक कहा कि किसानों को फर्टेलाइजर नही मिलौ। इसके बारें में समझता हूं कोई किल्लत नही है मेरे नोटिस मे कोई बात अभी तक नही आयी और हम ने इसके लिये बिल्कुल ठीक अमाउन्ट भी रखा है। अगर किसी को इसके बारें में कोई शिकायत है वह मेरे नोटिस में ला सकता है। और मै विश्वास दिला सकता हूं कि उस पर गौर किया जायेगा।

मार्किटिंग कमेटी का इन्तजाम बिल्कुल बिगड़ा हुआ हैं इसके बारें में जिक्र किया गया है मै इस बात की बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं हमारे पास इस बात का रिकार्ड है कि पिछली

सरकार ने इन सारी इलैक्टिड पंचायत समितियों को खत्त कियाजो डिवैल्पमेंट के काम करती थी। वे बड़ा अच्छा काम करती थी और दूसरे काम करती थी लेकिन मै आपकों यकीन दिलाता हूं कि अब वह धांधली नही चलने देंगे हम बहुत जल्दी ही पंचों, सरपंचों के इलैक्शन कर लेगे। इन मार्किटिग कमेटियेां के पास बड़ा पैसा होता है वे उस पैसे को डिवैल्पमेंट के कामें पर लगा सकते है जैसे सड़कों की जमीदारों को किल्लत होती है। किसानों की मंडियों में अनाज पहुंचाने के लिय बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वे रास्ते कच्चे होते है। इसलिए उस पैसे से विलेज रोड ओर लिक रोडबनाये जोय।

अब मै खेती के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब तक हम खेती बाड़ी की तरफ पूरा ध्यान नही देंगे तब तक हम अपने प्रांत को आग्र नही ले जा सकते है। इन सब बातां को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर पर इस बाजट का 72परसेंट से भी अधिक रूपया खर्च किया जायेगा। मै उन सब मैम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होने कुछ सुझाव दिये है। मै साथ ही साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई बात रह गयी है तो मै हर वक्त उनकी अच्छी सूटेबल बातें मानने के लिये तैया रहूं बाद में भी मुझे वे सुझाव दे सकते है इन सुझावों पर खासतौर से ध्यान दिया जायेगा ओर उनकी हरेक बात जो खेती–बाड़ी के लिय हरिणणे मे सूटेबल होगी उसको अमल में लाया जायेगा।

लोक कार्य मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिमांड नम्बर नौ परकाफी मेरे फाजिल दोस्त बोल चुके है। उन्होने कुछ रोशनी डाली है, फूड सप्लाई के सिलसिले में। जहां उन दोस्तों ने नुक्ताचीनी की है वहां कुछ सुझाव भी दिये है। मै उन दोस्तों का बेहद मश्कूर हूं जिन्होने ये सुझाव दिये है। मै उन दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जा भी सुझाव मेरे सामने आये है मै और यह महकमा उन पर पूरी तरह से गौर करेगा और यह महकमा जनता की पूरी सेवा करने की कोशिश करेगा।

चौधरी ईश्वर सिंह जी ने शूगर के सिलसिले में बताया है कि गांवों और शहरों के कोटे में फर्क नही होना चाहिय। मै भी मानता हूं कि यह फर्क नही होना चाहिये लकिन चूंकि हमारे पास चीनी की किल्लत है और पिछली सालों से उस के मुताबिक कोटा रखा गया ै। मै उन साथियों का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ज्यों ही चीनी की कमी पूरी होगी ह हम दोनों बिल्कुल बराबर कर देंगे और हमारी ख्वाहिश यह है कि अगर सैट्रल गवर्नमेंट मान गयी, हम सैट्रल गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट कर रहे है और हमें उमीदहै कि वह मान भी जायेगी, हम तो यह चाहते हकि यहां पर चीनी से राशन ही खत्म कर दिया जाये।

दूसरा सुझाव यहां पर कई भाईयों ने खासतौर पर यह दिया कि इस महकमें में बड़ी धांधली मची हुई है, कुरप्शन है, कुछ भाईयों ने यह भी फरमाया है कि कीमतें पूरी नही मिली है। मै चन्द एक मिसाले आप को देता हूं कि कुछ जगहों पर शुरू शुरू में मंडियों में शिकायते आयी और उसी के मुताबिक हमने एक्शन ले लिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकों यह जान कर खुषी होगी कि जहां भी किसी भाई ने शिकायत की हमने उसी वक्त पूरी जांच पड़ताल की और साथ ही जहां पर जिस किसी की कोई कमजोरी मिली। हमने या तो उसको सस्पेंड किया है या हमने कुछ एक को सविसिज को टरमीनेट किय है या जो सुस्त थे उनको ंएक जगह से दुसरी जगह पर ट्रांस्फर कर दिया गया हैं ओर उक्लाना मंडी के कुछ आढ़तियों के लाइसेंस फोरफीट किये गया है। और कुछ और लोग है जिनकी सविसिजज टरमीनेट की हैं इसी तरह से हमने एक्षन लिया है और मै अपने फाजिल मेम्बरान ओर दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि जब भी इस बरें मे कोई खास मिसाल उनके नोटिस में आये तो वे जरूर बताये। फिर कुरप्शन और अनाज की कम कीमत मिलने की बात की । आप को यह जानकर खुशी होगी कि जहां पिछले साल पंचास हजार टन अनाज प्रोक्योर किय गया था वहां इस सरकार ने ढाई महीने मे ंही 2.03 लाख टन अनाज प्रोक्योर किया है मंडियों मे इस दफा कुल 2.90 लाख टन अनाज आया जिसमें से 2.03 लाख टन प्रोक्योर किया गया है। यह सिर्फ ढाई महीन मे ंही किया गया था। यह भी आप को जानकार खुखी होगी कि यहां मैक्सीकन

सैटलमेंट के बारें में चर्चा हुई। फाइनेन्स मिनिस्टर ने इस विषय में काफी रोशनी डाल दी है। और यह सही है कि जहां पर सैटलमेंट पिछले 40 साल से नही हुआ है वहां पर इसे कब तक टालते रहेंगे। सैटलमेंट से मै समझता हूं कि किसी को नुकक्सान नही है। उसका होना जरूरी है।

एक बात जो सरदार तेजा सिंह ने कही कि मै ने यह कहा है कि अगर किसी सिख को हरियाणा में रहना है तो मेरे जैसा हो क रहे। यह बात बिल्कुल गलत है, मैने कभी ऐसा नही कहा। ओर जो मिनिस्टर बनाने की बात हैवह भी सत्य पर आधारित नही है। मैने कभी उनको ंमिनिस्टर बनाने के लिये नही कहा। एक बार कुछ आकाली लोगज रूरी मेरे पास आए थे औरउनके तीरके से मैन यही समझा कि वह शरारती इंसान है। उन्होने कहा कि हरियाणे के कुछ इलाके सिखों की बस्ती के है। यह जब तक पंजाब में वापस नही चल जो जब तक हमारे में ये उनको कोइ नुमाइन्दा सिख मिनिस्टर होना चाहिये। मैने कहा कि गवर्नमैट कांग्रेस पार्टी की है। आप अकाली है, हमारा विरोध करके इलैक्शन मे जीत कर आए है आप कैसे यह समझते है कि मै आपकों मिनिस्टर बनाऊंगा। आप चुपचाप यहां से चले जाइए। कोई सिख मिनिस्टर नही बनाना है। जा सिख हरियाणा में रहते है उनकी हिफाजत कांग्रेस खुद कर लेगी।

सरदार तेजा सिंह कांग्रेस पार्टी के आफिस में दो दफा मिलने आए। और आज उनको ंजो तकलीफ हुई उसका कारण मै,

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपे जरिए सदन को बतानाचाहता हूँ डन्होने कहा कि आप संत फतेह सिंह जी को एक चिट्ठी लिख दे कि मैने यह नही कहा कि अगर सिखों को हरियाणा मे रहना है तो मेरे जैसे बन कर रहें। तो मेने उनकों कहा कि संत फतेह सिंह कौन है, जिनकों मे चिट्ठी लिखूं और फिर जो बात गलत है उसका जिक्र तुम यहां क्यो करते हो। तो सरदार तेजा सिंह ने कहा कि क्या मै यह बात अखबार मे छाप दूं कि आपने ऐसी बात नही कही। मैने कहा कि बेशक छाप दो, फिर सरदार तेजा सिंह ने मेरे गोड़ों का हाथ लगा कर कहा कि हम एक अखबार चलाते है। आप उसकी मद कीजिए और हमारा जो अकाली दल का ग्रुप है। उसकी मदद कीजिए और उसे पैट्रनाइज कीजिए। मैने साफ इन्कार कर दिया। उसके बाद उन्होने कुछ सरकारी अफसरों के तबादलां की बात कही वह भी मैने कहा कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ऐसी बातें न तो मै सरदार तेजा सिंह की पूरी कर सकता हूं ओर न और किसी। एक बात मै और सदन को साफ कर देना चाहता हूं कि जो हरियाणा के कुछ इलाकों में सिख भाई बसते है उनमें यह अकाली लोग गड़बड़ी करेगा उसकों उचित ढंए स डील किया जायेगा। जो भी कोई हरियाणा के इंट्रेस के खिलाफ फिजा पैदा करेगा उसको टालरेट नही किया जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात और सरदार तेजा सिं हने यहां की जो बड़ी इन्सल्टिग थी। वह यह कि हरियाणा का सूबा अकालियों के कारण बना। मुझे क्या यह तो सभी का पता है

कि मास्टर तारा सिंह और सारा अकाली दल ने जाने कब से पंजाबी सूबे क लिय आवाज उठाता रहा मगर उनकी आवाज मेंकभी जान नही रही ओर वह कभी पूरी नही हुई। यह तो हरियाणा तब बना और पंजाबी सूबा भी अकालियों को तब मिला जब हरियाणा के लोगें ने यह आवाज उठाई कि हमारा हरियाणा हमें दिया जाए। संत फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह के हाथ तो बहुत पहले से देखते चले आ रहे थे, मगर कुछ नही हुआ था। उनकी आवाज को तो बहुत पहले दबा दिया गया था।

फिर अपोजीशन के मेम्बर साहिबान ने बड़े जोर से नारा नगाया कि यह सरकार तो हरिजनों को और देहातियेां को मरवाना चाहती है। मै आपके जरिये उन्हें बतला देना चाहता हूं कि अपोजीशन वाले ही देहातियों के ओर हरिजनों के ठेकेदार न बनें। उन्हें पता होना चाहिए कि यह अपोजीशन की ही सरकार थी जिससे देहातियों के ऊपर टैक्स लगाए और हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये ओर उन्हे ंदबाया। आज वह ऐसे नारे लगा कर जो चीप पापुलैरिटी हासिल करना चाहते है। वह नही मिलेगी क्योंकि हरिजन और देहाती इन की असलियत को जान गए है। कांग्रेस सरकार ने यह जो बजट पेश किया है। वह देहातियों और हरिजनों के हित के लिये है। अपोजीशन के लीडर और उनके साथियों ने बड़े जोर से यह काह कि सरकार लोगों को ऐक्सप्लयाट करना चाहती हे। और आज नही तो कलटैक्स लगाएगी यह खदशात जाहिर यि लेकिन मै सदन को यह विश्वास

दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार देहता क लोगों पर टैक्स लगाने का काई नही रखती।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इंडस्ट्री के बारें में सदन का ध्यान आकषित करना चाहता हूं कि यह सरकार गवर्नमेण्ट आफ इंडिया से इंडस्ट्री को ऐस्टेब्लिश करने के इरादे से कुछ नैगोशिएन कर रही है ओर सोनीपत, पलवल, रोहतक बहादुरगढ़, और फरीदाबाद ओर गुड़गांव, में इंडस्ट्रीज स्थापित की जांएगी और इन्हें जी.टी. रोड से मिलाने का भी इरादा है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बीच मे मै एक और बात और कह देना चाहूंगा। चौधरी मुख्तियार सिंह जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि सोनीपत मे कई एकड़ जमीन सरकार एक्वायर कर चुकी है। मै उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नही है, इतनी जमीन नही एक्वायर की गई और न ही इतनी की जाएगी, जितनी जरूरत समझी जाएगी सिर्फ उतनी ही की जाएगी। डिप्टी स्पीरकर साहिबा, मै हाउस का यह भी बताना चाहूंगा कि हम ने समालस्केल इंडस्ट्री को फिरोग देने के लिये करनाल और रोहतक मे इन्डस्ट्रीयल कालोनीज बनाने का विचार किया है, गुड़गांवा में जो पहले इंडस्ट्री सैटअप की गई है। वहा कुछ और इन्सैंटिव देकर उसको बढ़ाने का ख्याल है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से एक्सपर्टस बुलाकर अभी हिसार जिला में भेज है जो यह देखेगे कि कौन कौन–सी इंडस्ट्री वहां पर लग सकती है। जब वह वहां का दौरा करकरे वापिस आ जायेगे तो उसके बाद उनकों हरियाणा

के दूसरे हिस्सों में भेजा जाएगा और जहां जहां से जो इंडस्ट्री लगाई जा सकेगी वह वहां पर लगाई जाएगी। अम्बाले की बात खान साहिब ने कही और पीछे राम प्रकाश जी भी कर रहे थे, मै अर्ज करूं कि अम्बाला को भी पदी न्ही छोड़ा जाएगा। इन शब्दों के साथ मै सदन से प्रार्थना करूंगा कि डिमांड्ज को पास कर दिया जाए।

Extension of Sitting

Deputy Speaker: Hon. Members, before I put the Cut Motions and Demands to the vote of the House, may I have your consent to extend the sitting of the House by then minutes?

Voice: Yes, Yes, Madam

Deputy Speaker: The Sitting of the House is extended by ten minutes.

DEMNADS FOR GRANTS (Resumption) (Concld)

DEMNAD NO. 9

Deputy Speaker: I will now put to the vote of the House cut Motions and Demands. There is cut motion on Demand No. 9 by Shri Roop Lal Mehta.

Shri Roop Lal Mehta: I withdraw my cut motion, Madam.

Deputy Speaker: Has the hon. Members leave of the House to withdraw his cut motion.

Voice: Yes, yes, Madam

Deputy Speaker: The Cut motion is withdrawn with the leave of the House. I will now put Demand No. 9 to the vote of the House.

Question is —

That a sum not exceeding Rs. 1,3196,090 be granted to Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 64,16,940 already voted on account) in respect of charges under head 19-General Administration.

The motion was carried

DEMNAD NO. 19

Deputy Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,64,17,610 be granted to the Governor to detray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the

amount of Rs. 1,30,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 31—Agriculture.

The motion was carried

DEMNAD NO. 21

Deputy Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 39,18,570 be granted to the Governor to detray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 18,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 34—Co-operation.

The motion was carried

DEMNAD NO. 22

Deputy Speaker: There is a cut motion on Demand No. 22 by Shri Roop Lal Mehta which I will put to the vote of the House.

Shri Roop Lal Mehta: I withdraw may cut motion, Madam.

Deputy Speaker: Has the Hon. Member leave of the House to withdraw his cut motion.

Voice: Yes, yes, Madam

Deputy Speaker: The cut motions withdrawn with the leave of the House. I will now put Demand No. 22 to the vote of the House.

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 62,54,580 be granted to the Governor to detray the charges that will come in the course of payment for the year 1968-69 (excluding the amount of Rs. 40,00,000 already voted on account) in respect of charges under head 35—Industries.

The motion was carried

Deputy Speaker: The House now stands adjourned till 9-30 A.M. on Thursday, the 25the July, 1968

(The House then adjourned till 9-30 A.M. on Thursday, the 25th July, 1968)